04 - जेन जेड : भारतीय राजनीति में नई पीढ़ी की दस्तक

05 - स्कूलों की चौखट पर ठहरी गुणवत्ता

A Daily News Magazine

भोपाल

बुधवार, 10 जून, 2026

06 - उप मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, सहायक ग्रेड-3 एवं अनुकंपा नियुक्त...

07 - अपात्र हितग्राहियों के नाम हटाकर पात्र व्यक्तियों को जोड़ा...

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 278, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

क्या राहुल गांधी एक वैचारिक विपक्ष खड़ा कर सकते हैं?

शीतल पी. सिंह

पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव केवल यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार चुनाव जीत रही है। उससे भी बड़ा बदलाव यह है कि भाजपा और उसके वैचारिक आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने देश की राजनीतिक बहस की दिशा तय करने की क्षमता हासिल कर ली है। आज राजनीति में कौन से मुद्दे प्रमुख होंगे, किस भाषा में बहस होगी और जनता किन सवालों को महत्वपूर्ण मानेगी, इस पर उनका गहरा प्रभाव दिखाई देता है।

इसके मुकाबले विपक्ष की राजनीति बिखरी हुई, रक्षात्मक और कई बार विरोधाभासों से भरी नजर आती है। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए INDIA गठबंधन बनाया गया था। उद्देश्य था कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी दल मिलकर लड़ें। लेकिन शुरू से ही इस गठबंधन के भीतर एक बड़ी समस्या मौजूद रही है–कई क्षेत्रीय दल भाजपा से जितना सावधान रहते हैं, उतना ही कांग्रेस से भी। आज यह विरोधाभास और स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

INDIA गठबंधन में अनेक प्रकार के दल शामिल हैं। कुछ सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, कुछ क्षेत्रीय पहचान की, कुछ धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और कुछ केवल भाजपा विरोध के आधार पर साथ आए हैं। यह व्यवस्था चुनावी दृष्टि से उपयोगी हो सकती है, लेकिन वैचारिक दृष्टि से बहुत मजबूत नहीं है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी हैं। कई राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक-दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं। वामपंथी दलों और कांग्रेस का भी संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है। अनेक क्षेत्रीय दलों को यह डर भी रहता है कि यदि कांग्रेस मजबूत हुई तो भविष्य में वही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसलिए INDIA गठबंधन कई बार एक साझा राजनीतिक आंदोलन की बजाय अस्थायी समझौते जैसा दिखाई देता है।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी का विरोध करने के अलावा यह गठबंधन किस विचार के लिए खड़ा है? जनता केवल विरोध के आधार पर लंबे समय तक किसी गठबंधन का समर्थन नहीं करती। जनता को यह भी जानना होता है कि विकल्प क्या है।

विपक्ष के सामने नेतृत्व का प्रश्न लंबे समय से बना हुआ है। नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बाद में अलग रास्ता चुन लिया। ममता बनर्जी अपने राज्य में बेहद प्रभावशाली नेता हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक आंदोलन को राजनीतिक दल में बदला। अखिलेश यादव, एम.के. स्टालिन और अन्य क्षेत्रीय नेताओं का भी अपने-अपने राज्यों में मजबूत आधार है। लेकिन इन सभी नेताओं में एक समान सीमा है–इनमें से कोई भी पूरे देश में फैला हुआ राजनीतिक संगठन नहीं चलाता।

आज भी कांग्रेस ही एकमात्र विपक्षी दल है जिसकी मौजूदगी देश के लगभग हर हिस्से में है। उसकी ताकत कम हुई है, संगठन कमजोर हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उसकी उपस्थिति बनी हुई है। इसी कारण राहुल गांधी किसी भी राष्ट्रीय विपक्षी विकल्प की चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं। एक समय था जब उन्हें गंभीर राजनीतिक चुनौती नहीं माना जाता था। लेकिन 'भारत जोड़ो यात्रा' और 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के बाद उनकी राजनीतिक छवि में बदलाव आया है। उन्होंने बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और संवैधानिक संस्थाओं जैसे मुद्दों को लगातार उठाया है। कम से कम वैचारिक स्तर पर उनके पास एक स्पष्ट दिशा दिखाई देती है।

छोटा गठबंधन, लेकिन स्पष्ट विचार संभव है कि विपक्ष का भविष्य सभी दलों को एक छत के नीचे लाने में नहीं, बल्कि समान विचार वाले दलों को एक मंच पर लाने में हो। कल्पना कीजिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में एक ऐसा गठबंधन बने जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, वामपंथी दल और कुछ अन्य सामाजिक न्याय तथा धर्मनिरपेक्ष राजनीति में विश्वास रखने वाले दल शामिल हों। इस गठबंधन का उद्देश्य केवल सीटें जोड़ना नहीं होगा, बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक दृष्टि प्रस्तुत करना होगा।

इसका साझा कार्यक्रम निम्नलिखित मुद्दों पर आधारित हो सकता है– संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा, सामाजिक न्याय का विस्तार, जातिगत जनगणना, ओबीसी, दलित और आदिवासी प्रतिनिधित्व बढ़ाना, रोजगार आधारित आर्थिक नीतियाँ, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और समान नागरिक अधिकार, संघीय ढांचे को मजबूत करना तथा सामाजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को कम करना।

ऐसा गठबंधन शायद वर्तमान INDIA गठबंधन से छोटा हो, लेकिन उसका संदेश अधिक स्पष्ट होगा। वैचारिक स्पष्टता का मतलब राजनीतिक अकेलापन नहीं यह मान लेना गलत होगा कि यदि कोई गठबंधन स्पष्ट विचारधारा के आधार पर बने तो उसे हर चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। भारतीय राजनीति का अनुभव इसके विपरीत है। भाजपा स्वयं कई राज्यों में ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करती रही है जो उसकी पूरी विचारधारा से सहमत नहीं होतीं। चुनावी राजनीति में स्थानीय परिस्थितियाँ, सामाजिक समीकरण और व्यावहारिकता भी महत्वपूर्ण होती है।

इसी प्रकार सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित कोई विपक्षी गठबंधन अपनी वैचारिक पहचान बनाए रखते हुए राज्यवार चुनावी समझौते कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक विचारधारा और चुनावी रणनीति को अलग-अलग समझा जाए। विचारधारा दिशा देती है। चुनावी गठबंधन संख्या जुटाते हैं। दोनों की अपनी-अपनी भूमिका है। सामाजिक न्याय का अवसर हाल के वर्षों में सामाजिक न्याय का प्रश्न फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आया है। विपक्ष के पास इन मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाने का अवसर है। लेकिन इसके लिए उसे स्पष्ट और साहसपूर्ण रुख अपनाना होगा। विपक्ष के सामने असली चुनौती भाजपा की सबसे बड़ी ताकत केवल उसका संगठन नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी वैचारिक स्पष्टता है। उसके समर्थकों को पता है कि भाजपा किन मुद्दों के लिए खड़ी है। विपक्ष के सामने चुनौती है कि वह भी एक वैकल्पिक राष्ट्रीय कथा प्रस्तुत करे–ऐसी कथा जिसमें विकास और सामाजिक न्याय साथ-साथ चल सकें, राष्ट्रवाद और संवैधानिक मूल्यों में टकराव न हो, और लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने तक सीमित न रहे।

भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि ऐसे मोर्चे अक्सर किसी साझा विचारधारा से नहीं, बल्कि साझा विरोध से बनते हैं। नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय हित और वैचारिक मतभेद उन्हें लंबे समय तक टिकने नहीं देते। क्या वह युवाओं को यह विश्वास दिला सकता है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं? क्या वह सिद्धांतों पर आधारित राजनीति और व्यावहारिक चुनावी रणनीति के बीच संतुलन बना सकता है? यही प्रश्न आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति का भविष्य तय करेंगे। भारत को ऐसे विपक्ष की आवश्यकता है जिसे स्वयं पता हो कि वह किन मूल्यों, किन विचारों और किन उद्देश्यों के लिए खड़ा है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

उजालों के हसीं मंज़र ही
सारे छीन लेती है।
घटा तारिकियाँ देकर
उजाले छीन लेती है।।
मरासिम में दरारें डाल
कर ग़ुरबत के आलम में।
ये गर्दिश की घड़ी हमसे
हमारे छीन लेती है।।
बड़े होकर मिरे बच्चे
बग़ावत पर उतर आये।
समय की मार जीवन के
सहारे छीन लेती है।।
अभी बदले हुए दरिया का
तुमने रुख़ नहीं देखा।
कभी जब मौज बिफरे तो
किनारे छीन लेती है।।
अमीर ए शह्र के होते हुए
नफ़रत की ये आँधी।
ठिकाने छीन लेती है
गुज़ारे छीन लेती है।।
तिरा दीदार करना हो
गया दुश्वार ए' तन्हा'।
दरीचे पर हवा आकर
इशारे छीन लेती है।।

-सलीम तन्हा

कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार नटराजन का नामांकन खारिज

फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी कांग्रेस, विधायकों को लेकर बेंगलुरु जा रहा विमान रनवे से लौटा

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश कोटे की तीसरी राज्यसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। बीजेपी की आपत्ति पर रिटर्निंग ऑफिसर ने ये फैसला लिया है। दरअसल, भाजपा का आरोप है कि मीनाक्षी ने तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट में लंबित एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में छिपाई है। पर्यवेक्षक ने कारण बताओ नोटिस जारी कर आज शाम तक जवाब मांगा था।

इधर, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा- मीनाक्षी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है। उन्हें कोर्ट से केवल एक नोटिस मिला था। नामांकन रद्द होने के फैसले के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। नामांकन खारिज होने की जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधायकों को लेकर बेंगलुरू जा रहा विमान भी रनवे से लौट आया।

विधानसभा में गहमागहमी बढ़ी

दरअसल, नौ जून को राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र की स्क्रूटनी की जा रही है। इस दौरान बीजेपी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। बीजेपी का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन ने तेलंगना में अपने खिलाफ चल रहे मामले को छुपाया है। ऐसे में नामांकन पत्र को रद्द किया जाए। इसे लेकर विधानसभा में गहमागहमी बढ़ गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

तेलंगाना कोर्ट में ये है मामला

दरअसल, हैदराबाद कोर्ट में पूर्व पार्षद ए श्रीलता ने नटराजन के खिलाफ एक याचिका लगाई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि कुंभम शिव कुमार रेड्डी नाम के व्यक्ति को मीनाक्षी नटराजन संरक्षण दे रही है। रेड्डी पर ए श्रीलता ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। इसी मामले को लेकर बीजेपी ने विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की है।

जीतू पटवारी भी पहुंचे थे विधानसभा

वहीं, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भी विधानसभा पहुंच गए हैं। वहां धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई है। विधानसभा में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मीनाक्षी नटराजन पर कोई केस नहीं है। उन्हें सिर्फ नोटिस जारी हुआ है। बीजेपी सिर्फ इसे सियासी रंग दे रही है।

18 जून को है वोटिंग

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं। इनमें दो बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते की है। मगर बीजेपी के उम्मीदवारों तीनों सीटों पर इसलिए मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

मोहन कैबिनेट के फैसले

मंडी शुल्क में की बढ़ोतरी, भोपाल मेट्रो की राशि मंजूर ,कपास पर घटाई मंडी फीस

भोपाल (नप्र)। मोहन कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों और व्यापार जगत को गति देने के लिए कपास मंडी फीस की दर को एक फीसदी से घटाकर 0.5 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही भोपाल मेट्रो के निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई है।

मेट्रो निर्माण के लिए राशि मंजूर

कैबिनेट ने भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की मूल लागत 6,941.40 करोड़ में 3,092.22 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत जोड़कर संशोधित कुल लागत 10,033.62 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने इसके अतिरिक्त उद्योग के स्वीकृत मानदंडों के अनुसार परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए 3,532 करोड़ 22 लाख रुपये की भी स्वीकृति प्रदान की है।

2016 में बनी थी परियोजना, लागत बढ़कर पहुंची 10,033 करोड़- कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि भोपाल मेट्रो रेल परियोजना 2016 में तैयार की गई थी। उस समय इसकी अनुमानित लागत करीब 6 हजार 241 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 10,033 करोड़ रुपए हो गई है। परियोजना को गति देने और निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए बढ़ी हुई लागत को मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि अगले दो सालों में परियोजना का स्वरूप और अधिक स्पष्ट दिखाई देगा।

आईटी संवर्ग परामर्श सेवाओं के लिए राशि स्वीकृत

एमपी कैबिनेट ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत राज्य आईटी संवर्ग परामर्श सेवाओं के लिए अनुदान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की अवधि तक निरंतर संचालन के लिए 235 करोड़ 63 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार राज्य आईटी संवर्ग परामर्श सेवाओं के लिए अनुदान योजना के लिए 180 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंतर्गत शासन के विभिन्न विभागों, निगमों, प्राधिकरणों एवं परियोजनाओं को तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय आईटी संवर्ग का गठन किया गया है। योजना से प्राप्त अनुदान का उपयोग विशेषज्ञों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, क्षमता-विकास एवं विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप परामर्श सेवाओं के लिए किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना स्वीकृत- इसके साथ ही कैबिनेट द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य योजना के लिए 55 करोड़ 43 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। एमपीएसईडीसी जैसी नोडल एजेंसियों को सहायक अनुदान उपलब्ध कराकर विभिन्न आईटी एवं ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य, संभाग और जिला स्तर पर आयोजित कार्य शालाओं एवं सेमिनारों के माध्यम से विभागीय क्षमता संवर्धन तथा आईटी जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।

कपास पर मंडी की फीस आधा की- वहीं, कैबिनेट ने कपास जिनिंग मिलों की आवश्यकता को देखते हुए कपास पर मंडी फीस की दर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत करने का अनुमोदन दिया है। प्रदेश में लगभग 158 कपास जिनिंग मिलें है, जिनकी प्रसंस्करण क्षमता लगभग 13 लाख मीट्रिक टन है। प्रदेश में कपास पर मंडी फीस की दर में कमी किए जाने से जिनिंग मिलों के द्वारा अन्य पड़ोसी राज्यों में पलायन की अपेक्षा प्रदेश में ही व्यवसाय करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संज्ञान में लिया प्रारूप, शासकीय नौकरी में दो बच्चों की अधिकतम सीमा होगी समाप्त

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम में शासकीय नौकरी में दो बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी प्रावधान वाले प्रारूप नियम को निरस्त कर दिया है। साथ ही पोर्टल से विलोपित करने के आदेश भी जारी किए हैं।

गौरतलब है कि वर्ष 2001 में तत्कालीन राज्य सरकार के निर्णय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दो से अधिक जीवित संतान होने पर उम्मीदवारों को शासकीय सेवाओं की सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए अपात्र घोषित करने का प्रावधान था। वर्ष 2001 की प्रचलित व्यवस्था के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियमों के तहत 26 जनवरी 2001 या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान वाले उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिए अपात्र माने जाते थे तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखा गया था।

मानसूनी बारिश ने ठंडे किए भीषण गर्मी के तेवर

● यूपी में जगह-जगह पेड़ उखड़े, कर्नाटक में गाड़ियां बहीं ● मानसून ने देश के 13 राज्य कवर किए, आज मुंबई पहुंचेगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। मानसून 5 दिन में 13 राज्यों तक पहुंच गया है। सोमवार को तेलंगाना में एंट्री कर चुका है। फिलहाल यह मुंबई से करीब 150 किमी दूर है और अगले 48 घंटे में शहर में दस्तक दे सकता है। वहीं, अगले सप्ताह तक यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक पहुंच सकता है। मानसूनी हवाओं के असर से कई मैदानी राज्यों में गर्मी कम हुई है। साथ ही प्री-मानसून के कारण कई जगह 50-60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी और तेज बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मंगलवार को आंधी से कई जगह पेड़ उखड़ गए। केरल और कर्नाटक में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश जारी है। मंगलवार को बेंगलुरु और बेलगावी में भारी बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया। कुछ जगहों पर गाड़ियां पानी में बहती नजर आईं। इधर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में गर्मी का असर बना हुआ है। कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। सोमवार को श्रीगंगानगर का अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। केरलम में मानसून 4 जून को पहुंचा था। सोमवार को मानसून ने तेलंगाना में एंट्री कर ली। इससे पहले रविवार को मानसून त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड तक पहुंचा था। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 2-3 दिनों में यह बाकी इलाकों में आगे बढ़ सकता है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ बुधवार, 10 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

27वां कालांजलि कलोत्सव 12 जून को

भोपाल। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एवं पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित भोपाल की अग्रणी सांस्कृतिक संस्था कालांजलि ने अपने प्रतिष्ठित वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव '27वां कालांजलि कलोत्सव' आयोजित करने की घोषणा की है। इसे 12 जून को सायं 5:30 बजे रवीन्द्र भवन, भोपाल के हंसध्वनि सभागार में आयोजित किया जाएगा। यह अवसर भारतीय शास्त्रीय परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार के प्रति कालांजलि की 27 वर्षों की अविराम प्रतिबद्धता का गौरवपूर्ण उत्सव है।

वर्ष 1998 में प्रख्यात भरतनाट्यम आचार्य गुरु श्री प्रदीप कृष्णन द्वारा स्थापित कालांजलि आज केवल एक नृत्य संस्था नहीं, बल्कि एक सशक्त सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में विकसित हो चुकी है। लगभग तीन दशकों से संस्था भारतीय कला एवं संस्कृति की मूल आत्मा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। गुरु श्री प्रदीप कृष्णन के दूरदर्शी नेतृत्व में कालांजलि ने सैकड़ों विद्यार्थियों को न केवल नृत्य और संगीत की उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा प्रदान की है, बल्कि अनुशासन, समर्पण, विनम्रता और सांस्कृतिक चेतना जैसे मूल्यों का भी संस्कार दिया है। इसी कारण कालांजलि आज मध्य भारत के सर्वाधिक सम्मानित शास्त्रीय कला संस्थानों में अपनी विशिष्ट पहचान रखती। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक एवं पर्यटन सचिव डॉ. इलैयाराजा टी. (आईएएस) होंगे, जबकि भेल भोपाल के महाप्रबंधक रूपेश तेलंग विशिष्ट अतिथि रहेंगे।

कार्यक्रम का महत्वपूर्ण आकर्षण 'रंगप्रवेशम'

एमईआईएल ने हिमालय में बनाई 13 किमी टनल

सोनमर्ग/श्रीनगर। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एमईआईएल) ने मंगलवार को जोजिला टनल परियोजना में बड़ा मील का पत्थर हासिल करते हुए 13.153 किलोमीटर लंबी मुख्य टनल का अंतिम ब्रेकथ्रू पूरा कर लिया। इसके साथ ही बालटाल और मीनामार्ग की ओर से की जा रही खुदाई आपस में जुड़ गई। समुद्र तल से करीब 11,578 फीट की ऊंचाई पर बन रही यह दुनिया की सबसे लंबी सिंगल-ट्यूब, बाई-डायरेक्शनल रोड टनल मानी जा रही है।

इसके चालू होने के बाद श्रीनगर-कारगिल-लेह मार्ग पर 365 दिन आवागमन संभव होगा। वर्तमान में भारी बर्फबारी और हिमस्खलन के कारण जोजिला दर्रा सर्दियों में कई महीनों तक बंद रहता है, जिससे लद्दाख का संपर्क प्रभावित होता है। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के लिए एमईआईएल इस परियोजना का निर्माण कर रही है। अक्टूबर 2020 में शुरू हुई परियोजना अब सबसे महत्वपूर्ण चरण पार कर चुकी है। मुख्य टनल की खुदाई पूरी होने के बाद परियोजना परिचालन के काफी करीब पहुंच गई है।

माइनस तापमान और कठिन भूगर्भीय हालात में निर्माण– एमईआईएल ने टनल का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से किया है। अत्यधिक बर्फबारी, हिमस्खलन और जटिल हिमालयी भूगर्भीय परिस्थितियों के बीच यह कार्य पूरा किया गया। कंपनी के अनुसार परियोजना ने 1 करोड़ सुरक्षित मानव-घंटों का सुरक्षा रिकॉर्ड भी बनाया है।

टनल शुरू होने पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित होगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों तक रसद और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति आसान होगी। पर्यटन, व्यापार और सामरिक गतिविधियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा।

गडकरी बोले- भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण– केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जोजिला टनल भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि परियोजना में करीब 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों ने काम किया है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इसे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया।

संक्षिप्त समाचार

ईरानी बोट्स पर हमले के लिए तैनात अमेरिकी हेलीकॉप्टर क्रैश

- होर्मुज के पास हुआ यह हादसा, ट्रम्प बोले- दोनों पायलट सुरक्षित

तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलिकॉप्टर सोमवार को होर्मुज स्ट्रेट के पास क्रैश हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत के दौरान घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हेलिकॉप्टर में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं।

फिलहाल यह साफ नहीं है कि हेलिकॉप्टर तकनीकी खराबी के कारण गिरा या किसी हमले का शिकार हुआ। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले पर कल रिपोर्ट जारी की जाएगी। अमेरिकी सेना होर्मुज स्ट्रेट में अपाचे हेलिकॉप्टर, एमक्यू-9 रीपर ड्रोन, ए18 और एफ-35 लड़ाकू विमानों की मदद से सुरक्षा अभियान चला रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अपाचे हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल छोटे हथियारबंद बोट्स और ड्रोन के हमले रोकने के लिए किया जाता है।

ट्रम्प जो कहेंगे, नेतन्याहू को वही करना होगा– इजराइली लेखक गिडियन लेवी ने कहा है कि इजराइल अब सैन्य मदद के लिए अमेरिका पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर हो गया है। ऐसे में वह मिडिल ईस्ट के मामलों में अपनी मर्जी से फैसले नहीं ले सकता। अल जजीरा से बातचीत में लेवी ने कहा, इजराइल ट्रम्प को न नहीं कह सकता।

भारत ने पहली बार तैनात किए 12 परमाणु वॉरहेड

- रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, दशकों पुरानी नीति में बड़ा बदलाव

सिप्री की एक रिपोर्ट ने ऑपरेशनल तैनाती की कर दी है पुष्टि

नई दिल्ली (एजेंसी)। परमाणु हथियारों की नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए, भारत ने पहली बार 12 परमाणु वॉरहेड तैनात किए हैं। यह जानकारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट में सामने आई है।

दुनिया की प्रमुख हथियार-ट्रैकिंग संस्था सिप्री ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार तैनात किए हैं। यह दशकों से चली आ रही उस नीति से एक बड़ा बदलाव है, जिसके तहत परमाणु हथियारों और उन्हें पहुंचाने वाले सिस्टम को अलग-अलग जगहों पर रखा जाता था।

- **ऑपरेशन के लिए तैनात परमाणु हथियार–** रिपोर्ट का दावा है कि यह पहली बार है जब भारत के हथियारों के जखीरे को सिर्फ जमा करके रखने के बजाय, ऑपरेशन के लिए तैनात (ऑपरेशनली डिप्लॉयड) माना गया है। जमीन के नीचे बने मिसाइल साइलो और नई परमाणु पनडुब्बियों में तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार परमाणु हथियारों को तैनात करना, बढ़ी हुई तैयारी का संकेत देता है।

- **दशकों पुरानी नीति में भारत ने किया बदलाव–** रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में तैनात किए गए 12 वॉरहेड यह दिखाते हैं कि भारत ने पहली बार परमाणु वॉरहेड को डिलीवरी सिस्टम के साथ जोड़ा है या उन्हें ऑपरेशनल फोर्स वाले बेस पर तैनात किया है। इससे परमाणु हथियारों को अलग स्टोरेज सुविधाओं में रखने की उसकी दशकों पुरानी नीति में बदलाव आया है। सिप्री की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पिछले साल भारत के परमाणु हथियारों के भंडार में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी पर कुछ वॉरहेड तैनात किए गए हैं और डेटरेंस पेट्रोलिंग (रोकथाम के लिए गश्त) की गई है।

भारत के पास 190 परमाणु हथियार

सोमवार को जारी सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2026 तक भारत के पास लगभग 190 परमाणु हथियारों का बढ़ता हुआ भंडार होने का अनुमान था, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ी बढ़ोतरी है। ये हथियार एयरक्राफ्ट, जमीन से मार करने वाली मिसाइलों और परमाणु ट्रायड को सौंपे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है, लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि शांति के समय भारत अपने परमाणु वॉरहेड को तैनात लॉन्चरों से अलग रखता है। हालांकि, मिसाइलों को कैनिस्टर से संकेत मिलता है कि भारत शांति के समय में भी सक्रिय रहा है।

मणिपुर के गांवों में सुरक्षा बलों की एंट्री पर नई शर्त

- विलेज अथॉरिटी को पहले खबर देनी होगी, नगा गांव में हमले के बाद बढ़ा तनाव

इम्फाल (एजेंसी)। मणिपुर में 3 साल से जातीय हिंसा चल रही है। राज्य में पूरी तरह शांति नहीं है। सोमवार को कांगपोकपी जिले के पोंग्रिंगलॉन्ग रोंग्मेई नगा गांव में कुकी उग्रवादी संगठन ने गोलीबारी की। इस घटना के बाद लापता चुन्जांग्लुंग पान्मेई नाम के नगा विलेज गार्ड का शव जंगलों से मिला है। उसके सिर पर गोली मारी गई थी।

नगा समूहों का आरोप है कि केंद्र कुकी समूहों का इस्तेमाल शैडो वॉर (छाया युद्ध) के तौर पर कर रहा है। इसके अलावा चिंग मामांग गांव में अज्ञात हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें एक घायल हुआ है। नगा संगठनों ने सुरक्षा बलों पर पक्षपात का आरोप लगाया है। साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस बीच, नोने जिले के लोंग्जांग/ठंगाल गांव की विलेज अथॉरिटी ने राज्य पुलिस, असम राइफल्स, सीआरपीएफ को नोटिस दिया है। इसमें कहा है कि सूचना दिए बिना वे गांवों में नहीं आएं।

एनआरसी कराने की मांग को लेकर महिला महारैली

इम्फाल में सोमवार को 14 नागरिक संगठनों की महिलाओं ने 5 किमी तक महारैली निकाली। एनआरसी कराने और घुसपैठियों की पहचान कर बाहर करने की मांग को लेकर हजारों महिलाएं सड़कों पर उमड़ीं। मणिपुर में जारी हिंसा-तनाव की वजह से बड़ी संख्या में लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। आरटीआई से मांगी गई जानकारी में सामने आया है कि तीन साल में 731 विस्थापित अपनी जान गंवा चुके हैं। चूराचांदपुर में सबसे ज्यादा 248, बिष्णुपुर में 151 और कंग्पोक्पी में 128 मौतें दर्ज हुई हैं। जबकि राज्य के 9 जिलों में अभी भी 43,676 लोग विस्थापित हैं।

भगवान राम सभी को जोड़ते हैं, वही हमारे आदर्श हैं

- भारत के प्रति आस्था नहीं रखने वालों को लगाई जमकर लताड़

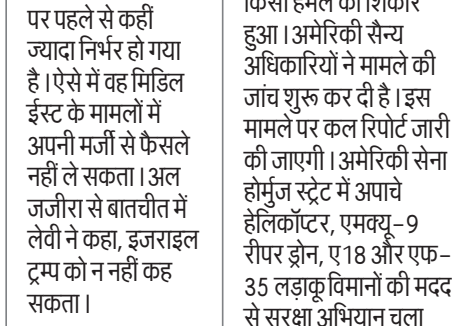

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामभद्राचार्य की राम कथा से बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा कि जो भारत के प्रति आस्था नही रखते, निष्ठा नही रखते, संस्कारो का सम्मान नही कर सकते, उन लोगो के लिए भारत की धरती धर्मशाला नही हो सकती। लखनऊ में 9 दिनों तक रामभद्राचार्य की राम कथा का आयोजन किया गया। मंगलवार को रामकथा का समापन हो गया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। रामकथा महोत्सव को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम सभी को जोड़ते हैं। सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम हम सबके आदर्श हैं। सीएम योगी ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि राम भक्तों ने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया।

आंदोलन को किया याद– सीएम योगी ने राम मंदिर के लिए चले आंदोलन को याद करते हुए कहा कि 500 वर्षो तक आंदोलन चलता रहा, 2019 में जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया तो उन्होंने स्वीकार किया जहां रामलला विराजमान हैं, वही रामजन्मभूमि है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का वक्तव्य था कि हमने रामभद्राचार्य जी के वक्तव्य को सुना तो हमें इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि कितने वर्षों से सनातन पर अत्याचार हो रहा था।

नर्सिंग की ट्रेनिंग लेने आई छात्रा की संदिग्ध मौत

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर के आईपीएस कॉलेज में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के तहत नर्सिंग ट्रेनिंग लेने आई 23 वर्षीय छात्रा नीलू प्रजापति पुत्री लक्ष्मण प्रजापति की मंगलवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। नीलू को सोमवार-मंगलवार दरमियानी रात करीब 12 बजे उल्टी होने लगी थीं। नीलू के परिजनों का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने समय से इलाज नहीं कराया। उसे बीमार होने के करीब 6 घंटे बाद (सुबह 6 बजे) अस्पताल ले जाया गया।

परिजनों का आरोप है कि हॉस्टल प्रबंधन की घोर लापरवाही ने उनकी बेटी की जान ले ली। छात्रा केआरजी कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और 45 दिन की विशेष ट्रेनिंग के लिए 14 मई को आईपीएस कॉलेज पहुंची थी। वह अपनी चचेरे भाई की बेटी तनु के साथ हॉस्टल में रह रही थी। परिजनों के अनुसार शुक्रवार को वह दो-तीन दिन के लिए घर भी आई थी और अपने खराब हो चुके जूते बदलवाकर वापस ट्रेनिंग के लिए कॉलेज लौट गई थी।

सोमवार देर रात करीब 12 बजे नीलू की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उसे उल्टियां होने लगीं। उसके साथ रह रही तनु ने फोन कर परिजनों को इसकी जानकारी दी।

पटाखा गोदाम में आग, 4 की मौत

जलने के बाद सड़क पर तड़पते रहे, लोग देखते रहे

जयपुर (एजेंसी)। जयपुर के खोह नागोरियान इलाके में स्थित पटाखों के गोदाम में मंगलवार सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई। अग्निकांड में बच्चे समेत चार लोगों की मौत हो गई और 4 मजदूर झुलस गए। मरने वालों में अब्दुल वाहिद शामिल हैं।

तीन की शिनाख्त नहीं हुई है। झुलसे आजीम खान (18), नासिर खान (20), समीर खान (20) और बिलाल (22) को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ये खोह नागोरियान में रहीम नगर के रहने वाले हैं। एसएमएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर

आरके जैन ने बताया- समीर और नासिर 95 फीसदी झुलस गए। बिलाल 75 और आदिब 65 फीसदी जल गया। जयपुर कलेक्टर संदेश नायक ने बताया- पटाखों का गोदाम खोह नागोरियान में आयशा नगर तलाई क्षेत्र आईटीआई कॉलेज के पास है।

- **विधायक बोले- क्या पुलिस को पता नहीं था–** विधायक अमीन कागजी ने कहा- रिहायशी इलाके में बारूद का गोदाम होने का क्या पुलिस को नहीं पता था। लोग भी किसके दबाव में हैं, जो बोल नहीं रहे हैं। यह किसका है, किसका नहीं, इस पर भी कोई जवाब नहीं है। मरने वाले राजस्थान के थे।

टीएमसी विधायकों की शिकायत पर ममता के घर पहुंची सीआईडी

- पुलिस आने के बाद एंट्री मिली, नेता विपक्ष के प्रस्ताव पर फर्जी हस्ताक्षर का आरोप

कोलकाता (एजेंसी)। टीएमसी में चल रहे विवाद के बीच मंगलवार को सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पहुंची। इसी परिसर में पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी है। शुरुआत में टीम को अंदर जाने से रोक दिया गया, लेकिन बाद में अतिरिक्त पुलिस बल की मौजूदगी में अधिकारियों ने परिसर में प्रवेश किया। टीएमसी के पूर्व सांसद सुभाषिश चक्रवर्ती ने कहा कि अभिषेक बनर्जी की गैर मौजूदगी में तलाशी की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि अभिषेक के आने के बाद एजेंसी जांच कर सकेगी।

- **अभिषेक के जवाब के आधार पर पहुंची टीम–** सीआईडी अधिकारियों के मुताबिक, अभिषेक बनर्जी ने एजेंसी के नोटिस के जवाब में बताया था कि विधायकों के हस्ताक्षर 30बी हरीश चटर्जी स्ट्रीट स्थित टीएमसी के केंद्रीय कार्यालय में जुटाए गए थे। यह कार्यालय ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास परिसर में ही है।

बांग्लादेशी घुसपैठियों को 'भगाने' पर बढ़ा तनाव

बीजीबी ने भारतीय सीमा पर तैनात किए ड्रोन, एक्सपर्ट ने दी धमकी

ढाका (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में कथित अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भगाने की घटनाओं के बीच बांग्लादेश की सेना ने सीमा की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजबी) की 55वीं बटालियन ने हबीगंज सीमा पर सुरक्षा अभियान तेज कर दिए हैं। इसके तहत थर्मल ड्रोन तैनात किए गए हैं और चौबीसों घंटे गश्त बढ़ा दी गई है। इसमें स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए जागरुकता अभियान भी शुरू किया गया है। सीमा पर ये डेवलपमेंट्स उस वक्त हो रहे हैं जब सोमवार को बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश का एक

प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा है। 11 जून तक चलने वाली ये बातचीत दोनों देशों की सीमा की सुरक्षा करने वाली फोर्स के बीच तनाव के माहौल में हो रही है। यह तनाव बांग्लादेश के उन आरोपों की वजह से है जिनमें कहा गया है कि बीजीबी कई जमीनी रास्तों से बिना कागजात वाले कथित बांग्लादेशियों को सीमा पार भेज रही है।

बांग्लादेश ने भारत से लगती सीमा पर तैनात किए ड्रोन

द डेली स्टार के मुताबिक बीजीबी-55 के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद तंजीलुर रहमान ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में हाईएस्ट लेवल का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा सीमा के हर हिस्से की सुरक्षा के लिए स्थानीय निवासी, ग्राम पुलिस और अंसार-बीजीबी के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। बीजीबी अधिकारी ने बताया कि रात में निगरानी के लिए थर्मल और इन्फ्रारेड ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही यार्ड मीटिंग का दायरा भी बढ़ाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पाने में विधायिका की भूमिका अहम : तोमर

भोपाल। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दृढ़ता और प्रतिबद्धता आवश्यक है। सरकारें और विधानसभाएं भी अपनी अपनी अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं। जनता की मानसिक रूप से तैयारी करवाना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जन जागरूकता होगी तो हम आधी लड़ाई वैसे ही जीत जाएंगे। इस कार्य मे विधायक और विधायिका की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि विधायक वास्तव में जनता और सरकार के बीच में सेतु है। अब अगर विधायक जागरूक हो कर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को भी जागरूक बनाने की दिशा में हम महत्वपूर्ण पहल कर पाएंगे। विधायकों की सक्रिय भागीदारी से हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अच्छे परिणाम पाने में सफल होंगे।

यह बात मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। वे हरियाणा विधानसभा में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटरी एसोसिएशन भारत क्षेत्र के ज़ोन-II सम्मेलन में बोल रहे थे। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण सहित

विभिन्न प्रदेशों की विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के जोन-2 सम्मेलन में विकसित भारत 2047: जागरूक समाज और विधायकों की भूमिका विषय की रूपरेखा रख कर मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सत्र का संचालन सूत्र थामा। विषय की रूपरेखा रखते हुए तोमर ने कहा कि जब विकसित भारत 2047 का लक्ष्य पाने की जिम्मेदारी की बात होती है तो हमको दूर तक सोच रखने की आवश्यकता है। अपनी सोच और दृष्टि उन कोनों तक ले जाने की जरूरत है जिन कोनों में अभी अभाव दिखाई दे रहा है। जिन कोनों पर काम करने की आवश्यकता है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की मजबूती और जवाबदेही की जब बात आती है तब चिंता होने लगती है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पाने के लिए राजनीतिक दृढ़ता और प्रतिबद्धता तो आवश्यक है ही, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होना भी आवश्यक है। इसके साथ ही सामाजिक और नागरिक जागरूकता जरूरी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। जनसंख्या प्रधान देश है। जनसंख्या हमारी ताकत है। उसमें भी हमारा यह सौभाग्य है कि आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। युवाओं की जो ताकत आज हमारे पास है, इस ताकत का संयोजन कैसे करना, इसका उपयोग कैसे करना तथा इस ताकत को दिशा कैसे देना और इसको कर्तव्यों की दृष्टि से अधिक जागरूक और सक्षम कैसे बनाना इस पर विधायक और विधायिका का योगदान महत्वपूर्ण रहने है। विधायक एक ऐसी पदवी है जो जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करती है। अगर विधायक जागरूक होंगे, अपने कर्तव्य का ठीक प्रकार से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जनता को भी जागरूक बनाने की दिशा में हम महत्वपूर्ण पहल कर पाएंगे।

इससे पहले सोमवार को हरियाणा विधानसभा में लोकतंत्र दीर्घा का उद्घाटन किया गया। तोमर ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के साथ हरियाणा विधानसभा की पुस्तकालय व्यवस्था का अवलोकन किया। चंडीगढ़ पहुँचे तोमर ने पंजाबी समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

बीजेपी का 'एमपी मॉडल', जिसके जरिए हर दिन सरकार और संगठन है कनेक्ट, ऐसे कैसे काम करता है यह

भोपाल (नप्र)। आम तौर पर किसी पार्टी वर्कर या आम आदमी को अपनी शिकायत लेकर मंत्री से मिलना एक मुश्किल काम होता है। लेकिन, राज्य बीजेपी मुख्यालय में हर दोपहर पार्टी वर्कर्स ससमेत कई लोग अपनी अर्जियों के साथ लाइन में लगते हैं। कुछ अपनी जमीन और घर से जुड़े लंबे समय से लंबित विवादों के समाधान की उम्मीद मे, तो कुछ सरकारी नौकरी में ट्रांसफर और प्रशासनिक दखल के मामलों को लेकर आते हैं।

छह महीने से पार्टी ऑफिस में बैठ रहे मंत्री– सभी विभागों के मंत्री अलग-अलग दिन पार्टी ऑफिस में लोगों की शिकायतें सुनते हैं। पार्टी के सहयोग सेल के तहत पिछले लगभग छह महीनों से चल रही यह पहल चुपचाप मध्य प्रदेश में बीजेपी की सबसे सक्रिय संगठनात्मक गतिविधियों में से एक बन गई है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि एक व्यवस्थित कार्यक्रम के तहत शिकायतें सुनने से पार्टी को जमीनी स्तर पर वर्कर्स के साथ जुड़ाव मजबूत करने में जरूरतमंदों तक पहुंचने में मदद मिली है।

पहले ही जारी हो जाता है रोस्टर– इस मॉडल की खास बात यह है कि इसे एक संस्थागत स्वरूप दिया गया है। पहले से ही एक मासिक रोस्टर जारी किया जाता है, जिसमें पार्टी वर्कर्स और लोगों को यह बताया जाता है कि कौन से मंत्री किस दिन उपलब्ध रहेंगे। इसकी वजह से भोपाल समेत प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से कार्यकर्ता आते हैं। साथ ही स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों से सिफारिश पत्र लेकर आते हैं। यह सुनवाई की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए काफी हद तक जरूरी होता है।

सहयोग सेल के तहत हो रहा है यह– राज्य बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि यह पार्टी सहयोग सेल के तहत हो रहा है। एक मासिक रोस्टर जारी होता है और हर दिन पार्टी कार्यालय में दो मंत्री रहते हैं। उनका काम यह सुनश्चित करना है कि यहां आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान हो। लोग रोस्टर देखकर उसके अनुसार आ सकते हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यहां आने वाले लोगों की समस्या का समाधान हो। लोग रोस्टर देखकर उसके अनुसार आ सकते हैं। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि वर्कर्स को इधर-उधर न भटकना पड़े। आम लोग भी यहां अपनी समस्याओं के साथ आ सकते हैं। यह सबके लिए खुला है।

3000 से ज्यादा अर्जिंया मिल चुकी

वहीं, बीजेपी के इस एमपी मॉडल से कैडर और कैबिनेट के बीच रोजाना का जुड़ाव है। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार अब तक 3000 से ज्यादा अर्जियां मिल चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा लंबे समय से लंबित मामलों के लिए सलाना ट्रांसफर विंडो खोलने के बाद वह संख्या और बढ़ गई है।

ट्रांसफर करवाने और फिर ट्रांसफर रद्द करवाने की मांग को लेकर आते

कई बार इसमें दिलचस्प किस्से भी सामने आते हैं। पार्टी के अंदरूनी लोग मजे लेकर सुनाते हैं। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि कुछ वर्कर्स बार-बार एक ही तरह की अव्यावहारिक मांगें लेकर आते हैं। ट्रांसफर के मौसम में, लोग ट्रांसफर करवाने के लिए आते हैं और बाद में उसी ट्रांसफर को रद्द करवाने के लिए वापस आते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के डेढ़ करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि शिकायतों के समाधान से कहीं ज्यादा, यह अपने विशाल कैडर को संगठन और सरकार, दोनों से सीधे जोड़े रखने का एक जरिया भी है।

बागमुगालिया इलाके में बवाल

हाईटेंशन लाइन के नीचे बसाई 60 झुग्गियां, भड़का जनता का गुस्सा

भोपाल (नप्र)। राजधानी के बागमुगालिया एक्सटेंशन इस वक्त प्रशासनिक तानाशाही का गवाह बना हुआ है। साल 2009 में कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस जमीन को हजारों पेड़ लगाकर 'ग्रीन बेल्ट' के रूप में विकसित किया था, आज उसे बेरहमी से उजाड़ा जा रहा है। आरोप है कि दीपक नगर की कीमती जमीन को किसी प्राइवेट बिल्डर के लिए खाली कराने के चक्कर में प्रशासन ने आनन-फानन में वहां के झुग्गीवासियों को इस ग्रीन जोन में शिफ्ट कर दिया।

मई के महीने में जहां सिर्फ 30 परिवार लाए गए थे, वहीं अब यह आंकड़ा 60 के पार पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का गंभीर आरोप है कि झुग्गियों का दायरा बढ़ाने के लिए यहां लगे पेड़ों को जानबूझकर केमिकल डालकर सुखाया जा रहा है, ताकि उन्हें आसानी से काटा जा सके।

हाईटेंशन लाइन का खौफ

इस पूरे री-सेटलमेंट ने न सिर्फ कॉलोनी के लोगों का जीना मुहाल किया है, बल्कि खुद उन गरीब झुग्गीवासियों की जान को भी आफत में डाल दिया है। जिस जगह पर इन झुग्गियों को बसाया गया है, ठीक उसके ऊपर से मौत बनकर दौड़ रही हाईटेंशन बिजली की लाइन गुजर रही है। कॉलोनी के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन एक तरफ पर्यावरण को तबाह कर रहा है और दूसरी तरफ इन गरीबों को मौत के कुएं में धकेल रहा है।

ताज्जुब की बात यह है कि इस गंभीर खतरे को देखने के बावजूद प्रशासन इसे सिर्फ एक अस्थायी व्यवस्था बताकर पल्ला झाड़ रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है।

सच छुपाने की नाकाम कोशिश

इस पूरे मामले में सरकारी महकमों की आपसी सिरफुटव्वल भी खुलकर सामने आ गई है। कोलार के एसडीएम प्रकाश चंद्र पांडेय जहां इस बात पर अड़े हैं कि हाईटेंशन लाइन से सिंगल-स्टोरी झुग्गियों को कोई खास खतरा नहीं है, वहीं बिजली कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर अनिल अग्रवाल ने उनके इस गैर-जिम्मेदाराना दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। बिजली विभाग का साफ कहना है कि हाईटेंशन लाइन के नीचे किसी भी तरह की इंसानी बस्ती बसाना बेहद खतरनाक है, चाहे मकान की ऊंचाई कितनी भी कम क्यों न हो। अफसरों की इस आपसी खींचतान से साफ है कि किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है।

ये सिर्फ बीजेपी में संभव: 6 साल के लिए पार्टी ने निकाला था, जमीन पर बैठे केवट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया

भोपाल (नप्र)। बीजेपी कब किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दे दे, कोई नहीं जानता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम के लिए जो मंथन चला, उस समय भी पार्टी ने मोहन यादव जो तीसरी पंक्ति में बैठे थे, उनको यह जिम्मेदारी दी। कमोबेश ऐसा ही हाल राजस्थान में हुआ। अभी राज्यसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने ऐसे ही नाम चुने हैं। तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल के बाद बीजेपी ने तीसरे उम्मीदवार के तौर पर महेश केवट को उतारा है। राजनीति का पहिया कितनी बेरहमी और अतरंगे ढंग से घूमता है, इसकी जीती-जागती मिसाल हैं महेश केवट।

2022 में किए थे पार्टी से बाहर– साल 2022 में निवाड़ी नगर परिषद चुनाव के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार को वोट देने के आरोप में बीजेपी ने जिन 11 नेताओं को 6 साल के लिए बाहर किया था, उनमें महेश केवट का नाम सबसे ऊपर था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। बीजेपी ने न सिर्फ उनका निष्कासन रद्द किया, बल्कि उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा देकर अब सीधे राज्यसभा के दंगल में झोंक दिया है। दिलचस्प बात यह है कि कभी पार्टी से बाहर कराने वाला यह '11' का आंकड़ा ही अब उन्हें संसद की दहलीज तक ले जा सकता है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं : एमडी यादव

गुणवत्ता में लापरवाही पर 8 निर्माण एजेंसियाँ होंगी ब्लैक लिस्टेड

भोपाल (नप्र)। प्रदेश में अधोसंरचना विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा नियमित रूप से किए जा रहे औचक निरीक्षण अभियान अन्तर्गत दिनांक 5 जून 2026 को मुख्य अभियंताओं के 7 विशेष निरीक्षण दलों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में निर्माणाधीन एवं पूर्ण हो चुके कार्यों का व्यापक निरीक्षण किया। रायसेन, सिवनी, दतिया, बड़वानी, शहडोल, रतलाम एवं पन्ना जिलों में निरीक्षण किया गया। इसमें कुल 35 निर्माण कार्यों का रेंडमली चयन कर उनकी गुणवत्ता, प्रगति, तकनीकी मानकों एवं रखरखाव की स्थिति का परीक्षण किया गया।

निरीक्षण किए गए कार्यों में 21 कार्य लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं पुल), 6 कार्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआईयू) के भवन निर्माण कार्य, 7 कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) तथा 1 कार्य मध्यप्रदेश भवन विकास निगम (एमपीबीडीसी) से संबंधित था।

मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के एमडी श्री भरत यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निरीक्षण दलों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में प्रमुख अभियंता (सड़क/पुल) श्री के.पी.एस. राणा, प्रमुख अभियंता (भवन) श्री एस.आर. बघेल, प्रमुख अभियंता (एमपीबीडीसी) श्री अजय श्रीवास्तव, तकनीकी सलाहकार श्री आर.के. मेहरा सहित प्रदेशभर के मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री एवं निरीक्षण दलों के अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित रहे।

एमडी श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना निर्माण, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की तकनीकी लापरवाही, निम्न गुणवत्ता अथवा अनुबंधीय शर्तों के उल्लंघन को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य केवल कमियों को चिन्हित करना नहीं बल्कि निर्माण गुणवत्ता में सतत सुधार सुनिश्चित करना है।

गंभीर अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई– एमडी श्री यादव ने कई कार्यों में गुणवत्ता संबंधी गंभीर कमियां पाए जाने पर संबंधित निर्माण एजेंसियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

शहडोल जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन भामौरी से पटना सड़क मार्ग के कार्य में गुणवत्ता संबंधी गंभीर कमियां पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने तथा निर्माण एजेंसी मेसर्स आशीष गुप्ता को मुख्य अभियंता रीवा परिक्षेत्र द्वारा ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए गए।

पन्ना जिले में करिया से महोद खुर्द मार्ग के निर्माण कार्य की गुणवत्ता असंतोषजनक पाए जाने पर संबंधित निर्माण एजेंसी मेसर्स आर.के. ट्रेडर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पन्ना को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार करिया से महोदकला सड़क निर्माण कार्य में गंभीर कमियां पाए जाने पर संबंधित उपयंत्री को नोटिस जारी करने तथा निर्माण एजेंसी मेसर्स कुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी, छतरपुर को ब्लैक लिस्ट में डालने के निर्देश दिए गए।

पन्ना जिले में ही मोहेंद्र-गोलही-पलोही मार्ग, जो परफॉर्मेंस गारंटी अवधि के अंतर्गत है, उसकी स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर निर्माण एजेंसी मेसर्स आर.एस. इन्फ्रा, सतना के विरुद्ध ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। रायसेन जिले में एसएच-15 से बासा-धामनपानी-कुचवाड़ा-किटुआ मार्ग के निर्माण कार्य में गंभीर तकनीकी कमियां पाए जाने पर निर्माण एजेंसी मेसर्स जगदीप सिंह एंड कंपनी, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध ब्लैक लिस्ट करने को कहा गया। अमरावद-चांदपुरा-भिश्ती से मोकलवाड़ा-पालका-श्री मार्ग की 7 किलोमीटर लंबी सड़क, जो परफॉर्मेंस गारंटी अवधि में है, की स्थिति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर वर्तमान एवं तत्कालीन अधिकारियों को नोटिस जारी करने तथा निर्माण एजेंसी मेसर्स चौधरी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, भोपाल को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए गए। रायसेन जिले के गैरतगंज स्थित विश्राम गृह निर्माण कार्य के निरीक्षण में गुणवत्ता संबंधी कमियां पाए जाने पर निर्माण एजेंसी मेसर्स शशि कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुरैना को ब्लैक लिस्ट में दर्ज करने के निर्देश दिए गए। सिवनी जिले में मध्यप्रदेश भवन विकास निगम द्वारा निर्माणाधीन गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल, धनोरा के कार्य में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आईं।

29 कार्यों में सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश

निरीक्षण के दौरान अधिकांश कार्यों में सामान्य अथवा आंशिक कमियां पाई गईं। एमडी श्री यादव ने ऐसे कुल 29 कार्यों में संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एमडी श्री यादव ने कहा कि आगामी निरीक्षणों में इन कार्यों की पुनः जांच की जाएगी तथा यदि कमियों का निराकरण नहीं पाया गया तो संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने विश्व योगासन चैम्पियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को दी बधाई

पहली विश्व योगासन चैम्पियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने लहराया परचम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहली विश्व योगासन चैम्पियनशिप 2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना की हैं। उल्लेखनीय है कि यह प्रतियोगिता हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर भारत की योग शक्ति का 'स्वर्णिम' परचम लहराया है। विश्व योगासन चैम्पियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने अद्भुत प्रदर्शन करते हुए 102 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 114 पदक जीतकर देशवासियों को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह सफलता भारत की समृद्ध ऋषि परंपरा, योग साधना और सांस्कृतिक चेतना की वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है।

डिंडोरी में पुलिस कस्टडी से भागा युवक

जंगल में मुंह में ठुंसे मिले बेशर्म के पत्ते, हालत देख कांप गए घरवाले

डिंडोरी (नप्र)। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शाहपुर थाना इलाके से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। रविवार रात करीब 10 बजे पुलिस कस्टडी से फरार हुआ उमेश कुमार सोमवार सुबह गोरखपुर डैम से लगे जंगल में गंभीर रूप से घायल और बेहोशी की हालत में मिला है। जब परिजन उसे ढूंढते हुए जंगल के भीतर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। उमेश झाड़ियों के बीच बेसुध पड़ा हुआ था और उसके मुंह के अंदर बेशर्म के पत्ते बुरी तरह ठूंसे गए थे। परिजनों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसके मुंह से वे पत्ते बाहर निकाले। उमेश का बायां पैर बुरी तरह सूजा हुआ है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उस पर बेरहमी से हमला किया गया है। हालत इतनी गंभीर है कि वह पुलिस के डर से अपने परिवार वालों से भी कुछ बोल नहीं पा रहा है।

मप्र पुलिस की महिला अफसर ने किलिमंजारो फतह किया

तंजानिया में 5865 मीटर ऊंचाई वाले ज्वालामुखी पर्वत पर चढ़ाई की, अब बना इतिहास

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश पुलिस की इंस्पेक्टर दीपिका गौतम ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो फतह कर नया इतिहास रच दिया है। वह मध्यप्रदेश पुलिस की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, जिन्होंने इस विश्व प्रसिद्ध पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। दीपिका भोपाल स्थित एससीआरबी (एससीआरबी) पीएचक्यू में पदस्थ है। उन्होंने 29 मई को करीब 5,895 मीटर ऊंची माउंट किलिमंजारो की चोटी पर पहुंचकर यह उपलब्धि हासिल की। खास बात यह रही कि इस अंतरराष्ट्रीय अभियान में वह भारत की एकमात्र प्रतिभागी थीं।

'सपनों को नहीं छोड़ा पीछे'– दीपिका कहती हैं कि नौकरी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अक्सर लोग अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका मानना है कि सपनों के बिना जिंदगी अधूरी होती है, और यही सोच उन्हें किलिमंजारो तक ले गई।

पांच दिन का कठिन अभियान– किलिमंजारो पर चढ़ाई पांच दिन का कठिन सफर था, जिसमें तीन बेस कैंप पार करने के बाद अंतिम चढ़ाई रात में शुरू हुई। इस दौरान तापमान माइनस 10 से 15 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम भी बेहद अनिश्चित था, जो हर पल बदल रहा था।

पहले कर चुकी हैं कई ट्रेक– हालांकि यह उनका पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय पर्वत अभियान था, लेकिन इससे पहले वह अमरनाथ और केदारनाथ जैसे धार्मिक ट्रेक कई बार कर चुकी हैं। खुद को मल्टीटास्किंग बताते हुए दीपिका लगातार नई चुनौतियों को अपनाने में विश्वास रखती हैं।

अगला मिशन जल्द– इस उपलब्धि के बाद अब उनका अगला लक्ष्य भी तय है, हालांकि उन्होंने इसे फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया है। संकेत दिए हैं कि अगले साल वह विदेश में एक और पर्वत अभियान पर जा सकती हैं।

बिजली उपभोक्ताओं से निरंतर संवाद बनाए रखें : ऋषि गर्ग

बिजली अवरूद्ध होने पर उपभोक्ता कॉल सेन्टर 1912, उपाय एप, व्हाट्सएप चेटबोट अथवा वेबसाइट पर दर्ज कराएं शिकायतें

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने उपभोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए फ्यूज ऑफ कॉल (विद्युत अवरोध को दूर करना) समय पर अटेण्ड करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध संचालक ने कहा है कि कंपनी के समस्त मैदानी अधिकारी अथवा कार्मिक अपने मोबाईल फोन को 24 घंटे चालू रखें। उन्होंने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसलिए बिजली कंपनी के सभी अधिकारी अपना मोबाईल 24 घंटे चालू रखें एवं उपभोक्ताओं के कॉल अटेण्ड करें। इसके साथ ही क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, संभागीय उपमहाप्रबंधक एवं सभी मैदानी अधिकारी कॉल सेन्टर 1912, व्हाट्सएप चैटबोट तथा स्थानीय वाट्सएप ग्रुप एवं अन्य माध्यम से प्राप्त होने वाली विद्युत संबंधी शिकायतों का तत्काल समाधान करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। प्रबंध संचालक ने सभी मैदानी अधिकारियों से कहा है कि वे सीआरएम पोर्टल पर सतत् निगरानी रखें और जनप्रतिनिधि तथा उपभोक्ताओं से संवाद बनाये रखें।

कंपनी ने कहा है कि आँधी, बारिश के दौरान एवं अन्य व्यवधान के कारण हुए बिजली फॉल्ट की शिकायतें दर्ज कराने के लिए कंपनी ने उपभोक्ताओं को अनेक विकल्प प्रदान किये हैं। अब उपभोक्ताओं के पास विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतों को दर्ज करने के लिए कॉल सेन्टर के टोल फ्री नंबर 1912, व्हाट्सएप नंबर 0755-2551222, मोबाइल एप 'उपाय (UPAY) अथवा कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in का विकल्प मौजूद है। उपभोक्ता इन विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प का उपयोग कर अपनी विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतें दर्ज कर आसानी से निराकरण करा सकते हैं।

संपादकीय

इंडिया गठबंधन : लक्ष्य अभी दूर

देश में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की 7वीं और दो साल के अंतराल के बाद दिल्ली में हुई बैठक का लब्बोलुआब यही है कि सभी ने भाजपा से लड़ने और नियमित अंतराल के साथ बैठकें करने का संकल्प जताया है। हालांकि पहले की तुलना में इंडिया गठबंधन की ताकत पहले के मुकाबले घटी है। पिछली बार इसमें 25 गैर भाजपा और गैर एनडीए क्षेत्रीय पार्टियों ने हिस्सा लिया था, इस बार संख्या घटकर 23 रह गई। क्योंकि डीएमके और आप ने इस गठबंधन से पहले ही खुद को अलग कर लिया था। चर्चा का विषय यह भी रहा तमिलनाडु में बंपर बहुमत से सत्ता में आई में टीवीके को इस बैठक में नहीं बुलाया गया। बीते दो साल में देश में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। इस बैठक में भी एसआईआर के मुद्दे को ज़ोरदार ढंग से आगे बढ़ाने के संकेत दिए गए। साथ ही संसद सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक करने का भी फैसला हुआ। इस बैठक में जिन पाँच अहम मुद्दों पर इस विपक्षी गठबंधन में सहमति बनी, उसमें एक प्रमुख मुद्दा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े से जुड़ा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया गठबंधन की नियमित बैठकें होती हैं और उसमें भाजपा से लड़ने की रणनीति बनती है तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर होगा। पहले की तुलना में अब अंतर यह है कि कांग्रेस दो साल पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत है और सभी दलों की अगुवाई की स्थिति में है। अपने अपने राज्यों में बुरी तरह हारने के बाद आरजेडी और टीएमसी जैसी पार्टियां कांग्रेस को झुकाने की स्थिति में नहीं हैं। दरअसल टीएमसी, डीएमके और सीपीआईएम के सत्ता से बाहर हो जाने से गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया था। ऐसे में जो बचा सकते हैं, उसे बचाने की कोशिश जारी है। लेकिन इंडिया गठबंधन को सचमुच प्रभावी ढंग से काम करना है तो उसे अपना पुख्ता ढांचा तैयार करना चाहिए। एक कार्यालय, कोई संयोजक और समन्वयकर्ता बनाना चाहिए। कुछ कमेटियां बनानी चाहिए। नेताओं को संयुक्त दौरे करने चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यस्तर पर समन्वय कैसे हो, इसका कोई रोड मैप तैयार करना चाहिए। उन मुद्दों पर मिलकर काम करना चाहिए, जिन पर सभी एकमत हों। अभी तो केवल एक ही समान लक्ष्य दिखता है और वो है भाजपा को हराना। हालिया बैठक में एसआईआर के मुद्दे पर भारत के प्रधान न्यायाधिपति को पत्र लिखने पर सहमति बनी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां एसआईआर को अपनी चुनावी हार से जोड़ रही हैं। लेकिन जिन राज्यों में गैर भाजपा पार्टियां जीतती हैं, वहां इस बारे में चुप्पी साध ली जाती है। मसलन केरल में कांग्रेस गठबंधन जीता तो वहां न एसआईआर समस्या हुई और न ही ईवीएम पर सवाल खड़ा किया गया। यही हाल तमिलनाडु का है। ऐसे दोहरे रवैये पर विपक्ष ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। इस बैठक में भी बुनियादी और विवादित मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा परस्पर सम्मान और स्वीकृति भी जरूरी है। राजनीति में जो पार्टी जीतती जाती है, वह दूसरी पार्टियों पर रौब गांठने लगती है। पश्चिम बंगाल में ममता की हार के बाद कांग्रेस दबाव बना रही है कि ममता अपनी पार्टी टीएमसी का विलय कांग्रेस में कर दें, जो शायद ममता बनर्जी कभी नहीं करेंगी। दिलचस्प बात यह है कि ये सभी पार्टियां लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हुई हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टियों में लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं है। सब नेताओं की मर्जी और भाई भतीजावाद पर केन्द्रित है। बैठक में शामिल नेताओं के चेहरों पर भी कोई चमक दिखाई नहीं दे रही थी।

जेन जेड : भारतीय राजनीति में नई पीढ़ी की दस्तक

नजरिया

अरुण कुमार डनायक
लेखक समाजसेवी हैं।

डिजिटल युग के भारतीय समाज में पीढ़ियों का वर्गीकरण अब अमेरिकी–मॉडल के आधार पर किया जाने लगा है, जबकि हमारे सामाजिकआर्थिक अनुभव उनसे भिन्न रहे हैं। यह ढांचा उपयोगी है, क्योंकि यह दिखाता है कि पीढ़ियाँ किन परिस्थितियों में बनीं और उनकी सामूहिक चेतना कैसे विकसित हुई। अमेरिका में यह मॉडल महामंदी, द्वितीय विश्व युद्ध, युद्धोत्तर विकास और सांस्कृतिक बदलावों से विकसित हुआ, जहाँ ग्रेटेस्ट जेनरेशन से लेकर जनरेशन अल्फ़ा की पहचान उनके समय की चुनौतियों और तकनीक के आधार पर की गई।

अमेरिका के विपरीत, भारत में पीढ़ियों का निर्माण तकनीकी या आर्थिक चक्रों से नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, राष्ट्र निर्माण, हरित क्रांति, बैंक राष्ट्रीयकरण, आपातकाल, उदारीकरण और डिजिटल क्रांति जैसे ऐतिहासिक मोड़ों से हुआ, जिन्होंने उनकी सोच, आकांक्षाओं और जीवन अवसरों को आकार दिया। इसलिए भारतीय पीढ़ियों को समझने के लिए स्थानीय इतिहास और सामाजिक अनुभव, जन्म वर्ष या तकनीकी परिवर्तनों के समान ही महत्वपूर्ण हैं। पिछली पीढ़ियों ने नेहरू युग की नीतियों और सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के विस्तार से स्थिर नौकरियाँ पाईं; जनरेशन एक्स ने उदारीकरण का लाभ तो देखा, पर सरकारी नौकरियों का सिकुड़ना भी। मिलेनियल्स आईटी बूम और निजी शिक्षा के दौर में बड़े हुए, जबकि जेनजेड आज एआई, परीक्षालीक, असुरक्षित रोजगार और तीव्र प्रतिस्पर्धा जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रही है। पुरानी पीढ़ियों को स्थिरता मिली, जबकि नई पीढ़ियाँ अवसरों के साथ अधिक असुरक्षा और प्रतिस्पर्धा भी झेल रही हैं। भारतीय साहित्य और सिनेमा में पीढ़ियों की समस्याओं का चित्रण हमेशा सामाजिक यथार्थ से गहरे जुड़ाव के साथ हुआ है। स्वतंत्रतापूर्व पीढ़ी की पीड़ा प्रेमचंद की 'गोदान' और 'गबन' में दिखती है, जहाँ ग्रामीण गरीबी और सामाजिक शोषण केंद्र में हैं। स्वतंत्रताबाद की पीढ़ी के संघर्ष हम लोग और रोटी, कपड़ा और मकान में उभरते हैं–मध्यमवर्गीय तंगी, दहेज, बेरोजगारी और बुनियादी जरूरतों की लड़ाई के रूप में। इसी समय परसाई, शरद जोशी और गोपाल चतुर्वेदी ने लाइसेंसपरमिट राज, भ्रष्टाचार और नौकरशाही पर तीखे व्यंग्य से सत्ता को बेनकाब किया । स्वदेश' और 'श्री इडियट्स' जैसी फिल्मों तथा चेतन भगत के उपन्यासों ने मिलेनियल्स की शिक्षा दौड़, ब्रेन ड्रेन, पारिवारिक दबाव, आईआईटी-आईआईएम प्रतिस्पर्धा और प्रेम-करियर द्वंद्व को लोकप्रिय संस्कृति में

प्रमुखता से प्रस्तुत किया। बांग्लादेश और नेपाल में 1997 के बाद जन्मी पीढ़ी द्वारा सत्ता परिवर्तन में निभाई गई भूमिका ने यह संकेत दिया है कि डिजिटल युग में जन्मी पीढ़ी जनरेशन ज़ेड भी व्यापक सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व कर सकती है ।

इसी पृष्ठभूमि में दिल्ली के जंतरमंतर पर काक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन भारतीय युवा राजनीति में एक अनोखा मोड़ बनकर उभरा। कुछ सप्ताह पहले तक एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन प्रतिक्रिया रहा यह अभियान अचानक छात्रों, अभिभावकों और युवा पेशेवरों की बड़ी भागीदारी वाले आंदोलन में बदल गया। सीजेपी का उभार भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरुद्ध आंदोलनों और सोशल मीडिया-आधारित छात्र असंतोष की व्यापक श्रृंखला का हिस्सा है, जो युवाओं के भविष्य को लेकर गहरी बेचैनी को दर्शाता है। इस अभियान के संस्थापक अमेरिका में अध्ययनरत अभिजीत दिपके ने जंतरमंतर के प्रदर्शन को 'ऐतिहासिक क्षण' बताया। उन्होंने सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम दिया कि यदि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते, तो आंदोलन फिर सड़कों पर लौटेगा। विगत एक सदी से भारत के कई परिवर्तनवादी आंदोलनों में गांधीवादी परंपरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस आंदोलन में सोनम वांगचुक की मौजूदगी ने इसे नैतिक आधार दिया, जिन्होंने शांतिपूर्ण प्रतिरोध और सत्याग्रह-उपवास जैसे गांधीवादी मार्ग अपनाने की अपील की। रील्स पोस्ट करने वाली पीढ़ी का अचानक सड़कों पर उतर आना बताता है कि युवा असंतोष अब पारंपरिक राजनीति से बाहर नई दिशा खोज रहा है। दूसरी ओर, सरकार ने इसे उच्चजोखिम घटना मानते हुए दिल्ली में भारी पुलिस बल और बहुस्तरीय बैरिकेडिंग तैनात की–साथ ही दिपके की ऑनलाइन गतिविधियों पर सवाल उठाए। यह स्पष्ट संकेत था कि सत्तातंत्र इस डिजिटलजनित आंदोलन को हल्के में नहीं ले रहा। भाजपा इस अभियान पर सख्ती से हमलावर रही। विदेश में बैठे लोगों के इस हस्तक्षेप को पार्टी ने स्वीकार नहीं किया और स्पष्ट किया कि वह लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेगी तथा युवाओं को किसी राजनीतिक एजेंडे का उपकरण नहीं बनने देगी। कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएँ भी एक समान नहीं रहीं। कांग्रेस की अपेक्षाकृत सतर्क प्रतिक्रिया कई प्रश्न खड़े करती है। संभव है कि इसके पीछे आंदोलन की राजनीतिक दिशा को लेकर अनिश्चितता, युवा असंतोष के प्रतिनिधित्व को लेकर प्रतिस्पर्धा, अथवा सोशल मीडिया आधारित नए आंदोलनों के प्रति पारंपरिक दलों की स्वाभाविक सावधानी जैसे कारण रहे हों। यह स्थिति संकेत देती है कि स्थापित राजनीतिक दल अभी भी डिजिटल माध्यमों से उभर रहे नए प्रकार के जन आंदोलनों की प्रकृति और संभावनाओं को पूरी तरह समझने की प्रक्रिया में हैं।

भारत के राजनीतिक इतिहास में जेपी आंदोलन, मंडल क्षण और अन्ना आंदोलन वे मोड़ रहे, जहाँ छात्रयुवा ऊर्जा ने सत्ता परिवर्तन की दिशा तय की–जनता पार्टी के उदय से लेकर सामाजिक न्याय की राजनीति और केजरीवाल के उभार तथा 2014 की लहर तक। पर इन आंदोलनों से निकली सरकारें अपेक्षित संरचनात्मक बदलाव नहीं ला सकीं: न जेपी आंदोलन कोई वैकल्पिक मॉडल गढ़ पाया, न अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार विरोध को संस्थागत सुधारों में बदल सका। मोदी सरकार भी, व्यापक अपेक्षाओं के बावजूद, शिक्षा, रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही में वह परिवर्तनकारी दिशा नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद 2014 में बनी थी। यह क्रम बताता है कि भारत में आंदोलन तो उभरते हैं, पर उनका राजनीतिक अनुवाद अक्सर अधूरा रह जाता है। सीजेपी जेनजेड के असंतोष को व्यक्त करता है, पर उसके पास न संगठित नेतृत्व है, न दीर्घकालिक एजेंडा, न कोई ऐसा सर्वमान्य नैतिक चेहरा जो आंदोलन को देशव्यापी दिशा दे सके। सोनम वांगचुक गांधीवादी तरीकों में विश्वास रखते हैं, पर 2014 के बाद जिस तरह षड्यंत्रपूर्वक लोगों को गांधी विचारों से दूर करने का प्रयत्न किया गया है, वह उनके मार्ग से नई पीढ़ी कितनी जुड़ पाएगी, यह स्पष्ट नहीं है। दिपके स्वयं को अंबेडकरवादी मानते हैं–ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आंदोलन की नैतिक दिशा गांधीवादी अहिंसा, अंबेडकरवादी सामाजिक न्याय या किसी नए डिजिटल लोकतांत्रिक मॉडल की ओर किस रूप में विकसित होती है। यदि यह अभियान केवल अपनी तात्कालिक मांगों तक सीमित रहा, तो आशंका है कि संरचनात्मक बदलाव के बिना पुरानी राजनीतिक शक्तियाँ 'वेश बदलकर' लौट सकती हैं। असली बदलाव तभी संभव है जब युवा शिक्षा, रोजगार, पारदर्शिता और कौशल पर दीर्घकालिक दृष्टि विकसित करें। इतिहास ने यह जिम्मेदारी अब जेन जेड के हाथों में सौंप दी है कि वह केवल विरोध की आवाज़ बने या परिवर्तन की दिशा भी तय करे।

भारत की बढ़ती परमाणु शक्ति

सिपरी रिपोर्ट-2025

प्रमोद भार्गव
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सिपरी यानी स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की ताजा रिपोर्ट में भारत की बढ़ती परमाणु शक्ति को रेखांकित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए हैं। जबकि भारत के पास कुल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर लगभग 190 हो गई हैं। भारत ने 2025 में सैन्य खर्च 92.1 अरब डॉलर किया है। इस कारण भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैनिक हथियारों पर खर्च करने वाला देश बन गया है। हथियार आयात करने में भी भारत दूसरे स्थान पर है। इस कड़ी में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन, चैथे पर भारत और पांचवें पर पाकिस्तान हैं। दुनिया के पास कुल 12.187 परमाणु हथियार हैं। इनमें सबसे ज्यादा अमेरिका के पास 5042 हथियार हैं। सिपरी के अनुसार भारत लंबी दूरी के हथियारों की संख्या बढ़ा रहा हैं, ताकि पूरे चीन तक भारत की मारक क्षमता मजबूत हो जाए। भारत की प्रतिद्वंद्विता पाकिस्तान से भी है। भारत परमाणु डिलीवरी सिस्टम पर भी काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य संघर्ष में भारत ने पहली बार साइबर मोर्चा भी खोल दिया था।

कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा 'बयान-बम' फोड़ा था। विवादित बयानों को लेकर चर्चित ट्रंप ने दावा किया था कि चीन और पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण में लगे हैं। रूस और उत्तर कोरिया भी परमाणु परीक्षण कर अपने हथियारों की ताकत टटोल रहे हैं। ये देश कभी भी यह बात स्वीकारने को तैयार नहीं हैं कि वे परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। ये देश भूमि की बहुत गहराई में परीक्षण करते हैं। इसलिए इनके परीक्षण की आहट किसी के कानों में नहीं गूंजती है। इन देशों के लोग खुले समाज के हिस्सा नहीं हैं, अतएव यहां की जानकारियां गोपनीय बनी रहती हैं। यह बात ट्रंप को इसलिए कहनी पड़ी, क्योंकि अमेरिका 30 साल बाद अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण फिर से करने का फैसला ले चुका है। इसलिए उन्होंने अपनी सरकार के फैसले को पाक और चीन के परीक्षणों के परिप्रेक्ष्य में तार्किक ठहराने के लिए कही है। यह बात ट्रंप ने न्यूज चैनल सीबीएस से बात करते हुए कही थी।

दरअसल रूस द्वारा ट्रंप से पूछा गया था कि 'क्या वे एडवांस न्यूक्लियर-कैपेबल सिस्टम, जिसके द्वारा पोसाइडन अंडरवाटर ड्रोन गतिविधि शामिल है, उसके परीक्षण के बाद परमाणु हथियारों का परीक्षण भी करेंगे?' इसके उत्तर में ट्रंप ने कहा था, 'उनके पास किसी भी दूसरे देश से अधिक परमाणु हथियार हैं। इन

हथियारों से दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है। हम इन्हें नहीं परखते। किंतु जब दूसरे देश परीक्षण कर रहे हैं, तब हमें भी करने की जरूरत है।' याद रहे, ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के बुसान नगर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने से पहले अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षणों को फिर से शुरू करने का बयान दिया था। पानी के भीतर पोसाइडन ड्रोन प्रणाली एक ऐसी तकनीक है, जिसमें रोबोटिक वाहन पानी के नीचे सक्रिय रहते हैं। ये स्वायत्त रूप से संचालित रहने के साथ इन्हें रिमोट के जरिए दूर से भी संचालित किया जा सकता है। ये ड्रोन पनडुब्बी वाहनों के समान होते हैं, जो बिना किसी मानव के पानी के नीचे संचालन और अनुसंधान के लिए होते हैं। किसी भी परमाणु हथियार संपन्न देश को परमाणु परीक्षण की जरूरत इसलिए होती है, क्योंकि परमाणु बम के लिए जरूरी यूरेनियम को संवर्धन (एनरिच) करना होता है। यह प्रक्रिया एक तकनीकी परीक्षण है। परमाणु परीक्षण की घोषणा किसी भी देश की ऐसी यौद्धिक रणनीति का हिस्सा है, जिससे वह शत्रु देश को अपनी ताकत का अहसास कराता है। भारत ने 1998 के बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। अब चीन और पाक द्वारा गोपनीय रूप में परमाणु परीक्षण की बात सामने आई है। अतएव इन देशों से भारत को परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। इसलिए भारत को भी अपनी परमाणु हथियार दागने की तकनीक का परीक्षण करना जरूरी हो गया है। हालांकि भारत का सिद्धांत पहले परमाणु हमला नहीं करने का रहा है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि अब हम इस वचन के पालन के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। पहले भी हमला कर सकते हैं। वैसे भी भारत ने अब तक परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने वाली संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। शायद इसीलिए टंऊम को कहना पड़ा है कि 'ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के विरुद्ध भारत परमाणु हमले के लिए तत्पर था। इस कारण पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुझसे निवेदन किया था कि आप बीच में आकर युद्ध रोकें, वरना पाक में लाखों लोग मारे जाएंगे।'

बहरहाल, ट्रंप के किसी भी दावे की पुष्टि भारत नहीं करता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया के कई देश न केवल परमाणु परीक्षण करने में लगे हैं, बल्कि घातक परमाणु हथियारों को इकट्ठा करने की होड़ में भी लगे हैं। स्टॉकहोम स्थित 'अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान' (एसआईआरआई) के एक अध्ययन ने दावा किया है कि चीन के पास 350, पाकिस्तान 165 और भारत के पास जनवरी 2021 तक 156 परमाणु हथियार मौजूद थे। हालांकि ताजा रिपोर्ट के अनुसार सभी देशों ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि कर ली है। ऐसा लगता है कि ये तीनों पड़ोसी देश अपने परमाणु शस्त्रागारों का विस्तार कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस समय 12,187 परमाणु हथियार दुनिया के देशों के पास हैं। इनमें 90 प्रतिशत से ज्यादा रूस और अमेरिका के पास हैं। इनके अलावा ब्रिट्रेन, फ्रांस, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास भी हथियारों का बड़ा जखीरा है। चीन परमाणु हथियारों की संख्या के बढ़ाने के साथ उनका तकनीकी रूप से आधुनिकीकरण भी कर रहा है। सऊदी अरब, मिश्र, भारत, आस्ट्रेलिया और चीन ने 2016 से 2020 के बीच सबसे ज्यादा हथियार आयात किए हैं। ट्रंप तो सरेआम कह रहे हैं कि उनके पास दुनिया को 150 बार तहस-नहस करने की परमाणु क्षमता है। यानी दुनिया परमाणु युद्ध के मुहाने पर खड़ी है।

अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए के पूर्व वरिष्ठ खुफिया अधिकारी केविन हलबर्ट की बात मानें तो पाकिस्तान दुनिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक देशों में से एक है। पाकिस्तान की यह खुंखार और डरावनी सूरत इसलिए बन गई है, क्योंकि तीन तरह के जोखिम इस देश में खतरनाक ढंग से बढ़ रहे हैं। एक आतंकवाद, दूसरे ढह रही अर्थव्यवस्था और तीसरे परमाणु हथियारों का जरूरत से ज्यादा भंडारण। आर्थिक संकट के ऐसी ही बद्दतर हालात से उत्तर कोरिया जूझ रहा है। मानव स्वभाव में प्रतिशोध और ईर्ष्या दो ऐसे तत्व हैं, जो व्यक्ति को विवेक और संयम का साथ छोड़ देने को मजबूर कर देते हैं। इस स्वभाव को क्रूरतम परिणति में बदलते हम अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए परमाणु हमलों के रूप में देख चुके हैं। अमेरिका ने हमले का जघन्य अपराध उस नाजुक परिस्थिति में किया था, जब जापान इस हमले के पहले ही लगभग पराजय स्वीकार कर चुका था। पाक इस समय इसी क्रूरतम मानसिकता से गुजर रहा है। ऐसे में यदि वह चीन के साथ परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। ट्रंप जो बात कह रहे हैं, वह हवा-हवाई होने की बजाय संभव है कि उनकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कही गई हो ? ट्रंप जैसे अविवेकी शासक पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है।

क्या चर्चिल अलेमाओ कांग्रेस में लौटेंगे?

राजनीति

डॉ. सुधीर सक्सेना
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

चर्चिल ब्राज अलेमाओ छोटे और तटीय राज्य गोवा के बड़े क्षत्रप हैं। वह धनाढ्य और रसूखदार शख्सियत हैं। वह चर्चित रहे हैं और विवादास्पद भी। उनके खाते में कई सुनहरी उपलब्धियां है। इनमें सर्वप्रथम हैं मुख्यमंत्रित्व। वह मार्च-अप्रैल, सन 1990 में गोवा के मुख्यमंत्री थे। सन् 1996-98 और सन 2004-07 में वह दक्षिण गोवा से निर्वाचित सांसद रहे। यही नहीं, इसके पूर्व वह बेनोलिम और नावेलिम निर्वाचन क्षेत्रों से चार बार राज्य विधानसभा के लिये चुने गये। कथानक दिलचस्प इस नाते हैं कि वह पहलेपहल सन् 1989 में राज्य विधानसभा के लिये चुने गये और अगले ही वर्ष उन्हें चीफ मिनिस्टर बनने का गौरव मिला। इसे नियति कहें या योगायोग कि वह केवल सत्रह दिन ही इस पद पर रह सके। कालक्रम के मान से वह प्रतापसिंह राणे के बाद गोवा के दूसरे मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्हें तकरीबन एक पखवाड़े में ही लुई बारबोसा को सत्ता सौंपनी पड़ी।

16 मई, सन 1949 को पोर्चुगीज गोवा में कार्मोना में जनमे चर्चिल ने बतौर सांसद और एमएलए खूब सुर्खियां बटोरीं। उन्होंने अपनी यात्रा यूनाइटेड गोवंस डेमोक्रेटिक पार्टी के बैनर तले शुरू की और विभक्त दल के संस्थापक बने। सन 80 के दशक के उत्तरार्द्ध में उसे अलविदा कह वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। कांग्रेसनीत प्रोगेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के सत्ता में आने पर वह चंद दिनों के लिये सूबे के मुखिया बने, किंतु आंतरिक खटपट से इस्तीफा देने को बाध्य हुये। बावजूद इसके कांग्रेस से उनका नाता जुड़ा रहा और वह उसी की टिकट पर चुने जाकर लोकसभा में पहुंचे। उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें कुछ न कुछ करने को प्रेरित करती रही। फलतः मार्च, 2007 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और सेव गोवा फ्रंट की स्थापना की। फ्रंट ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और दो पर विजय प्राप्त की। फ्रंट प्रत्याशी के तौर पर वह और अलीक्सो लौरेंसा विजयी रहे। चूंकि, स्पष्ट बहुमत किसी को भी नहीं मिला था, अतः कांग्रेस के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी तो फ्रंट उसका घटक दल था। चर्चिल को मंत्री पद मिला।

चर्चिल और उनके परिवार पर भाग्य अधिक दिनों तक मेहरबान नहीं रहा। मार्च, 2012 में असेंबली चुनाव में चर्चिल, उनके भाई जोआकिम, पुत्री वलांका और भतीजा यूरी चुनाव हार गये। चर्चिल ने अलेमाओ-परिवार के चार सदस्यों की पराजय पर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और ईवीएम पर तोहमत जड़ी। सन 2014 में वलांका के दक्षिण गोवा से टिकट देने पर इंकार करने पर उन्होंने कांग्रेस छोड दी और निर्दल लड़ने का ऐलान किया। दो ही दिन बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने की घोषणा की और उसकी टिकट पर लोकसभा के लिये चुनाव लड़ा, मगर मुह की खाई। उन्हें बमुश्किल करीब 12 हजार वोट मिले। इसके बाद उन्होंने फिर पैंतरा बदला और अक्टूबर, 2016 में एनसीपी में शरीक हो गये। यह दाँव उन्हें फला और सन 2017 में वह बेनोलिम से असेंबली के लिये चुने गये। इसके बाद भी वह चैन से नहीं बैठे और 13 दिसंबर, 2021 को टीएमसी में लौट आये।

ताजा चुनाव में टीएमसी के दयनीय प्रदर्शन और बिखराव के बाद 77 वर्षीय चर्चिल नया अशियाना तलाश रहे हैं। स्वभाविक तौर पर उनका ध्यान कांग्रेस की ओर गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उन्हें कांग्रेस में लौटने पर खुशी होगी। उनकी छोटी सी शर्त है, बशर्ते कांग्रेस 'एप्रोच' करे। वह साधन संपन्न कुबेर नेता हैं। इधर उन्हें कोंकणी-गायन का शौक चर्राया है। उनकी फुटबॉल टीम चर्चिल ब्रदर्स लीग मैचों में चर्चित रही है। बेटी वलांका इसकी सीईओ है। सन 2017 के चुनाव में उन्होंने करीब 15 करोड़ रूपयों की संपत्ति की घोषणा की थी। देखना दिलचस्प होगा कि एक और पारी खेलने को लालायित चर्चिल के लिये कांग्रेस अपने दरवाजे खोलती है या नहीं?

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

...और मोमबत्ती बरामद हुई

व्यंग्य

सुरेश सौरभ
लेखक व्यंग्यकार हैं।

दोस्तों यहां का मंजर मैं आप को जो दिखाने जा रहा हूं, उसे देख सुन कर आप लोगों के दिलों की धड़कनों की रफ्तार बिल्कुल राकेट की स्पीड जैसी बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर फुल स्पीड में बढ़ जाएगा। आप के कलेजे में, रोएं-रोएं में अजीब सी बिल्कुल सिरहन पैदा हो जाएगी। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि अच्छे समय पर बहादुर दल ने पुलिस को सही सूचना दे दी, वर्ना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। बहुत बड़ी घटना हो जाती, आप लोग देख रहे हैं कि पुलिस ने मौका-ए-वारदात पर एकदम से रेड मार दी है। आरोपी के पूरे घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रेड में बहुत से आपत्तिजनक धरम बदलने के आधुनिक समान बरामद हुए हैं ,जैसे जली अधजली मोमबत्ती, छोटी बड़ी देसी विदेशी 10 माचिसें ,18 नं बीड़ी का एक बंडल। देसी विदेशी नस्ल की जली अधजली सिगरेटों के टुड्डे, कुछ किताबें, चार मोबाइल,और दो लैपटॉप। पता यह भी चला है, कि यहां इस घर में धर्म बदलने का पूरा कारखाना चल रहा था, लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस घर में देश-विदेश से हर प्रकार का काला गोरा धन धड़ाधड़ बरस रहा था।

बैठे-ठाले उस दिन मेरा मन ऊबने लगा। मनोरंजन के लिए मैंने अपने मोबाइल पर आलतू-फालतू चैनल खोल दिया। चैनल पर एक एंकर तेज-तेज यानि सबसे तेज धुआंधार दहाड़ रहा था। 'दोस्तों मैं यहां फलाने गांव से सीधे आप से लाइव जुड़ रहा हूँ। इस गांव में पहुंचने के लिए मुझे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, न मैं आप को अपना मुंह खोल कर बता पाऊंगा, न आप कान खोल कर सुन पाएंगे।'

बहुत खतरनाक जंगली झांड़ियों, जर्जर दुर्गम पथरीले रास्तों से बचते-बचाते यहां पहुंचा हूं। यूं समझिए यह सारा किस्सा हालीवुड की किसी हॉरर फिल्म की तरह है।

दोस्तों यहां का मंजर मैं आप को जो दिखाने जा रहा हूं, उसे देख सुन कर आप लोगों के दिलों की धड़कनों की रफ्तार बिल्कुल राकेट की स्पीड जैसी बढ़ जाएगी। ब्लड प्रेशर फुल स्पीड में बढ़ जाएगा। आप के कलेजे में, रोएं-रोएं में अजीब सी बिल्कुल सिरहन पैदा हो जाएगी। यह तो बहुत अच्छा हुआ कि अच्छे समय पर बहादुर दल ने पुलिस को सही सूचना दे दी, वर्ना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। बहुत बड़ी घटना हो जाती, आप लोग देख रहे हैं कि पुलिस ने मौका-ए-वारदात पर एकदम से रेड मार दी है। आरोपी के पूरे घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। रेड में बहुत से आपत्तिजनक धरम बदलने के आधुनिक समान बरामद हुए हैं,जैसे जली अधजली मोमबत्ती, छोटी बड़ी देसी विदेशी 10 माचिसें,18 नं बीड़ी का एक बंडल। देसी विदेशी नस्ल की जली अधजली सिगरेटों के टुड्डे, कुछ किताबें, चार मोबाइल,और दो लैपटॉप। पता यह भी चला है, कि यहां इस घर में धर्म बदलने का पूरा कारखाना चल रहा था, लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस घर में देश-विदेश से हर प्रकार का काला गोरा धन धड़ाधड़ बरस रहा था।

आज देश में यह धर्म बदलने का काला धंधा बड़ी जोरों से चल रहा। देश को बांटने और काटने वाली ताकतों को बहादुर दल ने यहां बड़ी बहादुरी से बिलकुल नेस्तनाबूत करा दिया। हिमाचल सा महान है यह बहादुर दल। पर कुछ देश द्रोहियो के कलेजों में जलन मची पड़ी है, उनका कहना है कि गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण यह गोरख धंधा चल रहा है, पर मैं डंके की चोट पर कहता हूँ,कि यह सब सोची समझी बड़ी साजिशें हैं, जिसे हम कामयाब कतई न होने देंगे। हम देश विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों को अपने देश में कभी फलने-फूलने न देंगे। हम पूरी ताकत झोंक देंगे, ऐसे देश के गद्दारों को भगाने के लिए। दौड़ा-दौड़ा कर उन्हें कूटेंगे, देश से खेद देंगे ऐसे देशद्रोहियों को।

नीति आयोग की जारी शिक्षा रिपोर्ट

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

स्कूलों की चौखट पर ठहरी गुणवत्ता

शिक्षा के परिदृश्य को देखें तो आज शिक्षा के महकमे में लगभग 14.7 लाख स्कूल, 24 करोड़ से अधिक विद्यार्थी और लगभग एक करोड़ शिक्षक हैं। आकार के लिहाज से यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन इतनी विशाल व्यवस्था का वास्तविक मूल्यांकन भवनों, योजनाओं और नामांकन से नहीं, बल्कि इस सवाल से होना चाहिए कि क्या बच्चे वास्तव में सीख पा रहे हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में आज भी एक लाख से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ केवल एक शिक्षक है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक जीवंत विडंबना है। एक ही शिक्षक पहली से पाँचवीं तक की कक्षाएँ पढ़ाता है, जो उपस्थिति दर्ज करने के साथ मध्यान्ह भोजन की निगरानी, सरकारी पोर्टलों पर डेटा अपलोड करने और प्रशासनिक दायित्वों में भी व्यस्त रहता है।

भारत ने पिछले चार दशक में स्कूली शिक्षा के विस्तार की एक लंबी यात्रा तय की है। गांव-गांव स्कूल पहुँचे, नामांकन बढ़ा, बालिका शिक्षा में सुधार हुआ, बिजली, शौचालय, कंप्यूटर और स्मार्ट कक्षाओं जैसी सुविधाएँ तेजी से बढ़ीं। मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, छात्रवृत्तियाँ, स्कूल परिवहन, डिजिटल संसाधन और समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं ने शिक्षा के विस्तार को नई गति दी है। ऐसे में शिक्षा की तस्वीर बदली हुई दिखाई देती है। इसलिए स्कूल केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र का सबसे जीवंत प्रवेश-द्वार भी माना जाता है।

हाल ही में नीति आयोग की जारी रिपोर्ट 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडियाः टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी एन्हांसमेंट' शिक्षा से जुड़े अहम प्रश्नों को फिर से हमारे सामने रखती है। रिपोर्ट का सार जितना सरल है, उतना ही असहज करने वाला भी है। रिपोर्ट कहती है कि भारत ने स्कूलों तक पहुंच की लड़ाई काफी हद तक जीत ली है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की लड़ाई अब भी अधूरी है।

शिक्षा के परिदृश्य को देखें तो आज शिक्षा के महकमे में लगभग 14.7 लाख स्कूल, 24 करोड़ से अधिक विद्यार्थी और लगभग एक करोड़ शिक्षक हैं। आकार के लिहाज से यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कूली शिक्षा व्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन इतनी विशाल व्यवस्था का वास्तविक मूल्यांकन भवनों, योजनाओं और नामांकन से नहीं, बल्कि इस सवाल से होना चाहिए कि क्या बच्चे वास्तव में सीख पा रहे हैं?

नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में आज भी एक लाख से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ केवल एक शिक्षक है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक जीवंत विडंबना है। एक ही शिक्षक पहली से पाँचवीं तक की कक्षाएँ पढ़ाता है, जो उपस्थिति दर्ज करने के साथ मध्यान्ह भोजन की निगरानी, सरकारी पोर्टलों पर डेटा अपलोड करने और प्रशासनिक दायित्वों में भी व्यस्त रहता है।

हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि शिक्षक सिर्फ पाठ्यपुस्तकें नहीं पढ़ाते, वे सीखने का वातावरण रचते हैं। वे जिज्ञासा को दिशा देते हैं, बच्चों में आत्मविश्वास जगाते हैं और कक्षा को संवाद का जीवंत मंच बनाते हैं। लेकिन जब वही शिक्षक व्यवस्था शिक्षा के इतर कार्यों में उलझ जाता है, तो कक्षा में ज्ञान का संवाद स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ता है। शिक्षा तब पाठ्यक्रम पूरा करने की प्रक्रिया बनकर रह जाती है, सीखने की प्रक्रिया नहीं।

रिपोर्ट का दूसरा संकेत छोटे स्कूलों की ओर भी है। देश के लगभग 35 फीसदी विद्यालयों में 50 से कम विद्यार्थी हैं। इनमें से हजारों स्कूल ऐसे हैं, जहाँ दस से भी कम बच्चे पढ़ते हैं। पहली नजर में यह दूरस्थ इलाकों तक शिक्षा पहुँचने का प्रमाण लगता है। लेकिन दूसरी नजर में यह सवाल उठाता है कि इतने छोटे और अलग-थलग स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कैसे संभव होगा? बहुस्तरीय कक्षाएँ, सीमित संसाधन, कभी शिक्षक की अनुपस्थिति, कभी विषय विशेषज्ञों का अभाव–ये सब मिलकर शिक्षा को उपस्थिति तक सीमित कर देते हैं।

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में यह चुनौती और गहरी हो जाती है। कई स्थानों पर स्कूल भवन मौजूद हैं, लेकिन प्रयोगशालाएँ नहीं हैं; कंप्यूटर हैं, लेकिन इंटरनेट नहीं; पुस्तकालय हैं, लेकिन नियमित पठन संस्कृति नहीं। शिक्षा का ढांचा खड़ा है, पर उसके भीतर सीखने की आत्मा अभी भी कमजोर दिखाई देती है।

पिछले वर्षों में असर, नेशनल अचीवमेंट सर्वे और हालिया राष्ट्रीय मूल्यांकनों ने बार-बार यही संकेत दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने और गणित की बुनियादी दक्षताएँ चिंता का विषय बनी हुई हैं। तीसरी कक्षा का बच्चा दूसरी कक्षा का पाठ सहजता से नहीं पढ़ पा रहा। पाँचवीं कक्षा के विद्यार्थियों का एक बड़ा हिस्सा सरल भाग, प्रतिशत या अनुपात जैसी बुनियादी गणितीय अवधारणाओं में संघर्ष करता दिखाई देता है। नीति आयोग की रिपोर्ट भी स्पष्ट करती है कि केवल नामांकन पर्याप्त नहीं, सीखना शिक्षा का असली पैमाना है।

यह स्थिति केवल शैक्षिक कमजोरी नहीं है, यह उस बुनियादी सीखने के संकट की ओर संकेत है, जो आगे चलकर माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और रोजगार क्षमता तीनों को प्रभावित करता है। जब नींव कमजोर होती है, तो आगे की पूरी शैक्षिक संरचना अस्थिर हो जाती है। यही कारण है कि आज उद्योग जगत भी बार-बार कौशल अंतराल की बात करता है।

नीति आयोग की रिपोर्ट एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने लाती है सरकारी स्कूलों में भरोसे का धीरे-धीरे क्षरण। दो दशक पहले तक देश के अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। लेकिन आज स्थिति बदल रही है। वर्ष 2005 में जहाँ लगभग 71 फीसदी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा घटकर 49.24 फीसदी रह गया है। यानी पहली बार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का अनुपात आधे से नीचे चला गया है।

ग्रामीण परिवार, जो कभी सरकारी विद्यालय को स्वाभाविक विकल्प मानते थे, अब सीमित आय के बावजूद निजी स्कूलों की ओर देख रहे हैं। यह केवल विकल्प का बदलाव नहीं, बल्कि भरोसे का बदलाव है। अभिभावक अक्सर अंग्रेजी माध्यम, अनुशासन, नियमित उपस्थिति और अपेक्षाकृत बेहतर जवाबदेही को निजी स्कूलों से जोड़कर देखते हैं, भले ही वास्तविक गुणवत्ता हर जगह समान न हो।

यह प्रवृत्ति विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि सरकारी विद्यालय ही सामाजिक न्याय, अवसर की समानता और लोकतांत्रिक शिक्षा के सबसे बड़े माध्यम हैं। यही वे जगहें हैं जहाँ जाति, वर्ग, भाषा और आर्थिक असमानताओं के बीच लोकतांत्रिक सहअस्तित्व की पहली सीख मिलती है। यदि इन संस्थाओं पर भरोसा कमजोर पड़ता है, तो शिक्षा के साथ लोकतंत्र की बुनियाद भी कमजोर होती है।

माध्यमिक स्तर पर स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। रिपोर्ट माध्यमिक और उच्च-माध्यमिक स्तर पर एक और 'लीकेज' की ओर इशारा करती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को स्कूल तक लाने में सफलता मिली, लेकिन जैसे-जैसे कक्षाएँ बढ़ती हैं, बच्चे छूटते जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 11 फीसदी से अधिक बताई गई है। विशेष रूप से लड़कियाँ, आदिवासी समुदाय, प्रवासी परिवारों के बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सबसे पहले इस व्यवस्था से बाहर होते हैं।

इसके पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं हैं। किशोरावस्था में सामाजिक दबाव, बाल विवाह, सुरक्षित परिवहन की कमी, विज्ञान और गणित शिक्षकों का अभाव, स्थानीय स्तर पर करियर मार्गदर्शन की कमी और परिवारों की सीमित आकांक्षाएँ भी इस संकट को गहरा करती हैं। यह संकट केवल संसाधनों की कमी का नहीं, बल्कि शासन और प्राथमिकताओं का भी है। शिक्षक रिक्तियाँ वर्षों तक भरी नहीं जातीं। कई राज्यों में अतिथि शिक्षक और संविदा शिक्षक व्यवस्था स्थायी समाधान बनती जा रही है। स्कूल प्रधानाचार्य प्रशासनिक बोझ में दबे हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक नेतृत्व कमजोर है। रिपोर्ट में नीति आयोग ने कुछ समाधान भी सुझाए हैं। उनमें शिक्षकों की समयबद्ध नियुक्ति, छोटे स्कूलों का तर्कसंगत पुनर्गठन, स्कूल नेतृत्व को मजबूत करना, डिजिटल संसाधनों का प्रभावी उपयोग, सीखने के परिणामों की नियमित निगरानी और शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण जैसे कदम महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन देश में शिक्षा सुधार का इतिहास बताता है कि रिपोर्टें अक्सर नीति दस्तावेज़ बनकर रह जाती हैं। असली बदलाव तब होगा जब जिला शिक्षा कार्यालय से लेकर कक्षा-कक्ष तक जवाबदेही की संस्कृति बनेगी।

विडंबना यह है कि भारत में शिक्षा सुधार का संकट नीति का कम, क्रियान्वयन का अधिक रहा है। योजनाएँ बनती हैं, बजट स्वीकृत होते हैं, लक्ष्य तय होते हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर असमान दिखाई देता है। शिक्षा में सुधार केवल नई योजनाओं से नहीं, बल्कि पुरानी योजनाओं के ईमानदार क्रियान्वयन से भी आएगा।

भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है। लेकिन कोई भी राष्ट्र अपने स्कूलों की गुणवत्ता से आगे नहीं निकल सकता। सड़कें, मेट्रो, डिजिटल प्लेटफॉर्म और औद्योगिक निवेश विकास की पहचान हो सकते हैं, पर बेहतर भविष्य अंततः कक्षा-कक्ष में ही तैयार होता है। नीति आयोग की यह रिपोर्ट दरअसल एक सांख्यिकीय दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है। अगर स्कूलों में सीखना नहीं बदला, तो स्कूलों तक पहुंच की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए आज शिक्षा के सामने सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं या नहीं, बल्कि यह है कि स्कूल पहुँचने के बाद क्या वे सचमुच सीख रहे हैं?

खेल

लोकेंद्र नामजोशी

लेखक स्तम्भकार हैं।

भारतीय शतरंज के इतिहास का स्वर्णिम दौर

भारत के शतरंज में सिरमौर बनने की यह यात्रा आज शुरू नहीं हुई है। इसके लिए हमें कई दशकों तक इंतजार करना पड़ा। इसका श्रेय आधुनिक भारतीय शतरंज के जनक माने जाने वाले विश्वनाथन आनंद को दिया जाए तो यह कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने खेल-कौशल और बड़े टूर्नामेंट जीतने की अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर इस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। आनंद भारत के पहले ग्रैंडमास्टर बने और पांच बार विश्व चैंपियन बनकर उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी विश्व शिखर तक पहुंच सकते हैं। आनंद की सफलता ने देशभर में शतरंज की नई पीढ़ी तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया।

अभी हाल ही में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदा ने नॉर्वे में आयोजित विश्व के सबसे प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंटों में से एक 'नॉर्वे चेस' का खिताब जीतकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि शतरंज के खेल में भारत के स्वर्णिम युग का आगाज हो चुका है, जिसकी नींव कई दशक पहले रखी गई थी। शतरंज के खेल में आज भारत पूरे विश्व के सामने एक नई चुनौती बनकर उभरा है और पूरे वैभव के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। आर. प्रज्ञानानंदा की यह जीत केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय शतरंज के सुनहरे दौर का प्रतीक भी है।

यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि शतरंज जैसे बौद्धिक खेल का जनक माना जाने वाला भारत एक समय दूसरे देशों की तुलना में इस खेल में काफी पिछड़ा हुआ था। लेकिन धीरे-धीरे भारतीय खिलाड़ियों ने शतरंज के इतिहास में नई-नई इबारतें लिखना शुरू कर दीं। समय के साथ भारत में शतरंज के खेल ने ऐसी करवट बदली कि आज यह देश इस खेल की एक नई महाशक्ति बनकर उभरा है।

हालांकि भारत के शतरंज में सिरमौर बनने की यह यात्रा आज शुरू नहीं हुई है। इसके लिए हमें कई दशकों तक इंतजार करना पड़ा। इसका श्रेय आधुनिक भारतीय शतरंज के जनक माने जाने वाले विश्वनाथन आनंद को दिया जाए तो यह कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने खेल-कौशल और बड़े टूर्नामेंट जीतने की अदम्य इच्छाशक्ति के बल पर इस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। आनंद भारत के पहले ग्रैंडमास्टर बने और पांच बार विश्व चैंपियन बनकर उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को यह विश्वास दिलाया कि वे भी विश्व शिखर तक पहुंच सकते हैं। आनंद की सफलता ने देशभर में शतरंज की नई पीढ़ी तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया।

दरअसल, आनंद के बाद भारत में प्रतिभाओं की एक पूरी फौज तैयार हुई। हाल के वर्षों में डी. गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, निहाल सरीन, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा तथा महिला खिलाड़ियों में दिव्या देशमुख, कोनेरू हम्पी और आर. वैशाली जैसे खिलाड़ियों ने विश्व स्तर पर भारत का परचम लहराया है। विशेष रूप से गुकेश ने विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब केवल शतरंज प्रतिभाओं का उत्पादक देश नहीं, बल्कि विश्व शतरंज की नई महाशक्ति बन चुका है।

विश्व स्तर पर शतरंज में कुछ प्रतियोगिताएं ऐसी मानी जाती हैं, जिन्हें जीतना किसी खिलाड़ी के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। इनमें वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, फिडे विश्व कप, टाटा स्टील चेस

टूर्नामेंट, नॉर्वे चेस, चेस ओलंपियाड तथा विश्व रैपिड और विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप प्रमुख हैं। इन विश्वस्तरीय स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे है।

यदि पिछले कुछ वर्षों के परिणामों पर नजर डालें तो भारत के युवा खिलाड़ी लगातार विश्व की शीर्ष प्रतियोगिताओं में पदक और खिताब जीत रहे हैं। जूनियर, रैपिड, ब्लिट्ज और क्लासिकल–हर प्रारूप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज स्थिति यह है कि विश्व शतरंज के लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी खिताब के प्रमुख दावेदार माने जाते हैं।

भारत की शतरंज यात्रा को नई दिशा देने का श्रेय विश्वनाथन आनंद को जाता है। वे वर्ष 2000 में विश्व चैंपियन बने और बाद में 2007, 2008, 2010 तथा 2012 में भी विश्व खिताब अपने नाम किया। उन्होंने विश्व कप, विश्व रैपिड और विश्व ब्लिट्ज जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं भी जीतीं और भारत को शतरंज महाशक्ति बनने की राह दिखाई।

नई पीढ़ी में डी. गुकेश ने 2024 में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं हाल ही में आर. प्रज्ञानानंदा ने 2026 में नॉर्वे चेस का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वे यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय बने। महिला वर्ग में भी भारत ने उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की हैं। कोनेरू हम्पी दो बार विश्व रैपिड चैंपियन (2019 और 2024) बन चुकी हैं और वर्षों तक विश्व की शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल रही हैं। हरिका द्रोणावल्ली ने महिला विश्व चैंपियनशिप में कई बार पदक जीते हैं। इसी कड़ी में दिव्या देशमुख भी एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्होंने भारतीय महिला शतरंज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। दिव्या ने 2025 में महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रचा और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। वहीं आर. वैशाली ने 2026 में महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतकर महिला विश्व चैंपियनशिप की चुनौतीकर्ता बनने का अधिकार प्राप्त किया।

नॉर्वे चेस में प्रज्ञानानंदा की जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं है; यह उस सुनहरे दौर की घोषणा है, जिसमें भारत विश्व शतरंज का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। विश्वनाथन आनंद द्वारा बोया गया बीज अब एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। प्रज्ञानानंदा, गुकेश, अर्जुन एरिगैसी और महिला खिलाड़ियों सहित अन्य युवा सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वर्षों में विश्व शतरंज पर भारत का प्रभुत्व और अधिक मजबूत होगा। निस्संदेह, यह भारतीय शतरंज के इतिहास का सबसे स्वर्णिम दौर है।

सरोकार

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

मनुष्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रकृति का संदेश

विश्व पर्यावरण दिवस हो या कोई अन्य अवसर, पर्यावरण संरक्षण के लिए देश-दुनिया में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बच्चे जागरूकता रैलियां निकालते हैं, युवा मैराथन में भाग लेते हैं, सामाजिक संगठन वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं और विभिन्न वर्गों के लोग स्वच्छता तथा हरित जीवनशैली के समर्थन में अपनी भागीदारी दर्ज कराते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ये प्रयास केवल प्रतीकात्मक रह जाते हैं, या वास्तव में हमारे व्यवहार और विकास की दिशा को भी बदल पाते हैं?

कुछ वर्ष पहले कोरोना महामारी के दौरान पूरी दुनिया मानो ठहर-सी गई थी। उद्योग, परिवहन और बाजारों की गतिविधियां सीमित हो गईं। उस समय नदियों का पानी अपेक्षाकृत स्वच्छ दिखाई दिया, आकाश निर्मल हुआ, वायु प्रदूषण में कमी आई और वन्यजीवों की गतिविधियां भी पहले से अधिक दिखाई देने लगीं। प्रकृति ने मानो थोड़े समय के लिए अपनी मौलिकता का परिचय दिया। यह दृश्य सुखद था, किंतु क्या इसका अर्थ यह है कि पर्यावरण बचाने के लिए विकास की सारी गतिविधियां रोक दी जाएं? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से 'नहीं' है।

मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन, परिवहन, निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां अनिवार्य हैं। इनके कारण कुछ मात्रा में पर्यावरणीय प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब आवश्यकता की सीमा समाप्त होकर लालच की शुरुआत हो जाती है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जंगलों, नदियों, पहाड़ों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करने लगता है, तब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और उसके दुष्परिणाम अंततः मनुष्य को ही भुगतने पड़ते हैं।

इतिहास गवाह है कि प्रकृति समय-समय पर चेतावनी देती रही है, लेकिन मनुष्य अक्सर उन्हें अस्थायी घटनाएं मानकर भूल जाता है। कोरोना महामारी ने भी पूरी मानव सभ्यता को यह संदेश दिया कि तकनीकी प्रगति के बावजूद प्रकृति के सामने मनुष्य सर्वशक्तिमान नहीं है। उसने यह भी सिखाया कि सीमित साधनों में भी जीवन संभव है और उपभोग ही सुख का एकमात्र आधार नहीं है।

लॉकडाउन के दिनों में सामाजिक दूरी की बाध्यता के बावजूद अनेक परिवारों ने एक-दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर पाया। लोगों ने महसूस किया कि कठिन परिस्थितियों में परिवार, सहयोग और सामूहिक मनोबल सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि संकट के समय मनुष्य की प्राथमिकताएं अंततः रोटी, कपड़ा और सुरक्षित आश्रय तक सिमट जाती हैं। अपने घर लौटने के लिए संघर्ष करते प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा और असंख्य मार्मिक दृश्य आज भी हमारी स्मृतियों में अंकित हैं।

ऐसे अनुभव यह सोचने को विवश करते हैं कि क्या हमारी पारंपरिक जीवनशैली, सीमित आवश्यकताओं की संस्कृति और परिवार-केंद्रित सामाजिक व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें आधुनिक जीवन में पुनः अपनाया जा सकता है। इसका अर्थ अतीत में लौट जाना नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर वर्तमान को अधिक संतुलित बनाना है।

यह भी सच है कि त्रेता या द्वापर का समाज आज उसी रूप में वापस नहीं आ सकता। मानव सभ्यता ने लंबे संघर्ष, ज्ञान और विज्ञान के आधार पर वर्तमान का निर्माण किया है और भविष्य की यात्रा भी इसी मार्ग से आगे बढ़ेगी। इसलिए विकास को रोकना समाधान नहीं है, बल्कि विकास को प्रकृति के अनुकूल बनाना ही वास्तविक विकल्प है। निस्संदेह विकास की प्रक्रिया में कुछ पर्यावरणीय क्षति होती है, किंतु आज हमारे पास उसके प्रभाव को कम करने के अनेक वैज्ञानिक और व्यावहारिक उपाय उपलब्ध हैं। स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, वृक्षारोपण, कचरा प्रबंधन और टिकाऊ जीवनशैली जैसे कदम विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं।

आवश्यकता केवल संकल्पों की नहीं, बल्कि उनके ईमानदार क्रियान्वयन की है। हर वर्ष हम पर्यावरण संरक्षण की शपथ लेते हैं, पुराने संकल्प दोहराते हैं, लेकिन धरातल पर अपेक्षित परिवर्तन बहुत धीमा दिखाई देता है। अब समय केवल भाषणों और प्रतीकात्मक अभियानों का नहीं, बल्कि दूरदर्शी और ठोस कार्यों का है। हवा, पानी, पेड़-पौधे, नदियां, तालाब, पहाड़ और समूचा प्राणी जगत मानव जाति से संवेदनशील व्यवहार और दृढ़ संकल्प की अपेक्षा कर रहे हैं।

प्रकृति हमें बार-बार संदेश देती है। प्रश्न यह नहीं कि वह हमें कितना समझाती है, बल्कि यह है कि क्या हम उसकी चेतावनियों को समझकर अपने विकास और अपने भविष्य को अधिक संतुलित और सुरक्षित बनाने का साहस जुटा पाएंगे।

कलेक्टर की रात्रि चौपाल का दिखा सकारात्मक परिणाम, दिव्यांगजनों को मिला प्रमाण-पत्र, पेंशन की पहल

सोहागपुर। विगत दिनों सोहागपुर विकासखंड सोहागपुर के ग्राम कामती रंगपुर में आयोजित 'प्रशासन आपके द्वार - रात्रि चौपाल' कार्यक्रम का सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे है। उल्लेखनीय है कि रात्रि चौपाल के दौरान प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर नर्मदापुरम के निर्देशानुसार त्वरित कार्रवाई करते अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी ने दो दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लाक मेडीकल आफीसर डॉ रेखा गौर आदि हितग्राही उपस्थित थे। रात्रि चौपाल में ग्राम कामती निवासी कुमारी अर्चना पिता श्री जयराम (उम्र लगभग 11 वर्ष) एवं श्री देवेंद्र कुमार पिता श्री प्रहलाद (उम्र लगभग 62 वर्ष) द्वारा अस्थि बाधित (ऑर्थोपेडिक) दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। आवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर नर्मदापुरम ने दोनों प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल परीक्षण कर नियमानुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश दिए थे।कलेक्टर के निर्देशों के पालन में जिला चिकित्सा प्राधिकरण, नर्मदापुरम द्वारा दोनों आवेदकों का मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया गया। परीक्षण उपरांत दोनों आवेदकों को 40 प्रतिशत अस्थि बाधित

दिव्यांगता प्रमाणित पाए जाने पर दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी किए गए। एसडीएम सोहागपुर द्वारा दोनों हितग्राहियों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र वितरित किए । इसके साथ ही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि दोनों हितग्राहियों के ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक आवेदन तत्काल भरवाकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ दिलाने की कार्यवाही की जाए। हितग्राहियों एवं उनके परिजनों ने कलेक्टर नर्मदापुरम एवं जिला प्रशासन द्वारा की गई त्वरित, संवेदनशील एवं जनहितैषी कार्रवाई के लिए आभार व्यक्त किया। प्रकरण दर्शाता है कि रात्रि चौपाल के माध्यम से प्राप्त जनसमस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित कर शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, सहायक ग्रेड-3 एवं अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण की मांग

धार। मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री को विभिन्न कर्मचारी हितैषी मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शासन का ध्यान लंबे समय से लंबित महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर आकर्षित किया।

ज्ञापन में विभागाध्यक्षों एवं उनके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों को मंत्रालय, विधि एवं विधायी कार्य विभाग तथा राजभवन में कार्यरत सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान एवं ग्रेड-पे का लाभ प्रदान किए जाने की मांग की गई। संघ का कहना है कि समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को समान वेतन एवं अवसर मिलना चाहिए। वर्तमान में अधीनस्थ कार्यालयों के सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी आईएफएमआईएस, ई-ऑफिस, लेखा, बजट, ऑडिट, सूचना का अधिकार, निर्वाचन, जनगणना एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों

का निर्वहन कर रहे हैं, किन्तु उन्हें मंत्रालयीन कर्मचारियों के समान वेतनमान का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने एक अन्य ज्ञापन के माध्यम से अनुकंपा नियुक्त सहायक ग्रेड-3 कर्मचारियों की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। ज्ञापन में बताया गया कि सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता एवं नियम 6.5 के कारण अनेक अनुकंपा नियुक्त कर्मचारी सेवा से पृथक किए जा रहे हैं, जिससे मृत शासकीय सेवकों के परिवारों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। संघ ने मांग की कि अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए, सीपीसीटी संबंधी प्रावधानों का सरलीकरण किया जाए तथा सेवा से पृथक किए गए कर्मचारियों की सेवाएं पुनः बहाल की जाएं।

उप मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना तथा संबंधित विषयों पर शासन स्तर पर उचित विचार एवं आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सुनील कानुनगो, प्रांतीय सचिव गंगासिंह सिसोदिया, तहसील अध्यक्ष प्रितेश मालवीय, ओ.पी. सोनी, मुकेश वर्मा,सुनील वर्मा एवं आशीष चौरे सहित अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तारपूर्वक रखते हुए शीघ्र निराकरण की मांग की। उप मुख्यमंत्री द्वारा विषयों पर सकारात्मक विचार करने के आश्वासन से कर्मचारियों में आशा एवं उत्साह का वातावरण है। संघ ने विश्वास व्यक्त किया कि कर्मचारी हितों से जुड़े इन महत्वपूर्ण विषयों पर शासन सकारात्मक निर्णय लेकर हजारों कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को राहत प्रदान करेगा।

धार में 11 जून को इको केम्प आयोजित

धार। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के अंतर्गत धार के मातेश्वरी गार्डन में इको कैंप 11 जून गुरुवार को लगाया जाएगा । 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी भाग लेंगे । इस केम्प का उद्देश्य विद्यार्थियों मे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता स्थापित करना है। इको केम्प में विद्यार्थियों को गेम्स, वेस्ट से बेस्ट, क्विज कॉम्पीटिशन सहित और भी अनेक प्रकार की गतिविधि करवाई जाएगी। जो प्रतिभागी भाग लेना चाहे , वे आयोजक से निम्नलिखित 9893722678 मोबाईल नंबर पर सम्पर्क कर सकते है।

महावीर जैन के निधन पर परिजनों ने किये उनके नेत्रदान, धार नगर का 37वां नेत्रदान

धार। धार के म. गा. मार्ग निवासी 63 वर्षीय महावीर जैन के दुखद निधन पश्चात उनके परिवार द्वारा धार मानव सेवा कल्याण समिति के माध्यम से एवं भोज हॉस्पिटल धार के डॉ बौरासी और उनकी सहायिका कर्मा मुजालदा के

सहयोग से उनके नेत्रदान किये गए जो धार नगर का 37वां नेत्रदान है।समिति द्वारा इस पुण्य कार्य हेतु परिवार का आभार व्यक्त किया गया एवं महावीर जैन को श्रद्धांजलि दी गई। उल्लेखनीय है कि धार मानव सेवा कल्याण समिति धार नगर में विगत 3 वर्षो से रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान एवं देहदान के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर नगर की जनता को इस और जागरूक करने का कार्य कर रही है और इस कार्य में काफी हद तक सफल भी रही है। संस्था द्वारा अभी तक धार नगर और आसपास के ग्रामीण इलाको सहित 37 नेत्रदान, एक त्वचा दान और 3 देहदान करवाँ चुकी है। एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 लोगो को आँखों में रोशनी प्राप्त होती है। इस प्रकार अभी तक संस्था द्वारा 74 लोगों को आँखों मे ज्योति प्राप्त हो चुकी है। संस्था ने नगर के नागरिकों से इस अभियान में सहयोग की अपील की है।

युवा संगम के तहत रोजगार एवं उद्यमिता शिविर 18 जून को

बैतूल। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जयवंती हॉक्सर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैतूल के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में युवा संगम के तहत रोजगार, स्वरोजगार एवं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप रोजगार मेला तथा उद्यमिता शिविर का आयोजन 18 जून को किया जाएगा। प्राचार्य डॉ. मीनाक्षी चौबे ने बताया कि महाविद्यालय के अटल सभागार में प्रातः 1 से सायं बजे तक आयोजित मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से विभिन्न पदों पर चयन किया जाएगा। साथ ही उद्यमिता शिविर में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे। स्टॉल का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।

आठनेर महाविद्यालय में जागरूकता कार्यशाला आयोजित

विद्यार्थियों ने ली जल गंगा संवर्धन की शपथ

नदियों-तालाबों की स्वच्छता और पॉलिथीन मुक्त शहर पर हुआ मंथन

बैतूल। जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन को जनआंदोलन बनाने के उद्देश्य से पंडित द्वारका दास विज्ञान महाविद्यालय आठनेर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में 120 विद्यार्थियों ने सहभागिता करते हुए जल संरक्षण, पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। महाविद्यालय के संचालक आनंद राठौर के संरक्षण तथा प्रोफेसर चरण निरापुरे, प्रोफेसर शिवदयाल अमरूते और प्रोफेसर सत्येंद्र बोरबन की उपस्थिति में आयोजित कार्यशाला में जयवंती हाकसर महाविद्यालय बैतूल के पूर्व प्राध्यापक डॉ. सुखदेव डोंगरे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर (बिहार) के सहायक प्राध्यापक डॉ. अमित सातनकर ने जल संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. सुखदेव डोंगरे ने विद्यार्थियों और प्राध्यापकों को जल गंगा संवर्धन की शपथ दिलाते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी को जून-जुलाई में पौधारोपण कर पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। डॉ. अमित सातनकर ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जल ही जीवन है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर चरण निरापुरे ने नदियों और तालाबों को स्वच्छ बनाए रखने की आवश्यकता बताई, जबकि प्रोफेसर सत्येंद्र बोरबन ने आठनेर को पॉलिथीन मुक्त बनाकर स्वच्छ शहर के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर सत्येंद्र बोरबन ने किया तथा आभार प्रदर्शन प्रोफेसर शिवदयाल अमरूते ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रोफेसर कविता कापसे, प्रोफेसर भूपेंद्र बंजारे, प्रोफेसर पूजा अडलक, प्रोफेसर आयुषी, प्रोफेसर महेंद्र राठौर, प्रोफेसर घोरसे, प्रोफेसर बोहारा तथा छात्र-छात्राओं का सक्रिय सहयोग रहा।

घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में हो रहे रेत के अवैध भंडारण, परिवहन पर कार्यवाही

2 जेसीबी मशीन, 2 डम्पर एवं 7 ट्रैक्टर किए जप्त

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 8 जून को घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम चिखलपाटी की भड़ंगा नदी क्षेत्र में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण की सूचना मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के नेतृत्व में राजस्व, पुलिस एवं खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही करते हुए उक्त क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहपुर, तहसीलदार घोड़ाडोंगरी, नायब तहसीलदार चोपना, हल्का पटवारी, पुलिस थाना चोपना का पुलिस बल खनि निरीक्षक एवं सहायक खनि अधिकारी बैतूल द्वारा मौका निरीक्षण के दौरान उक्त नदी क्षेत्र स्थित शासकीय भूमि ख. क्र.475 रकबा 9.100 हेक्टेयर क्षेत्र में से रेत उत्खनन कर नदी के किनारे ग्राम चिकलपाटी की भूमि ख. क्र. 474 रकबा 64.947 हेक्टेयर मद बड़े झाड़ का जंगल में 02 अलग-अलग ढेर के रूप में खनिज रेत का अवैध भण्डारण करना पाया गया, जिसमें से एक ढेर में खनिज रेत की मात्रा 210 घन मीटर एवं दूसरे ढेर में खनिज रेत की मात्रा 120 घन मीटर पाई गई। इस प्रकार खनिज रेत की कुल मात्रा 330 घन मीटर का मौके पर भण्डारण पाया गया। इसके साथ ही मौके पर 07 ट्रेक्टर-ट्राली में से 03 ट्रैक्टर-ट्राली एवं 01 डम्पर खनिज रेत से भरा पाया गया। संयुक्त अमले द्वारा मौके पर कार्यवाही करते हुए अवैध रूप से भंडारित खनिज रेत मात्रा को जब्त करने के साथ अवैध भण्डारण, परिवहन में संलग्न मशीनऔर वाहनों को भी जब्त कर वाहन मालिकों, वाहन चालकों, अवैध भंडारण कथाओं के विरूद्ध खनिज नियमों के तहत कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही के दौरान मौके पर वाहनों के चालकगण, पुलिस थाना चोपना का पुलिस बल, ग्राम पंचायत सचिव नूतनडंगा, कोटवारगण एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। उक्त प्रकरण पर अवैध भंडारण कर्ताओं के विरूद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अर्थदण्ड की राशि प्रस्तावित कर प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल में प्रस्तुत किया जा रहा है।

अपर कलेक्टर ने जनसुनवाई में सुनीं नागरिकों की समस्याएं

जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने के दिए निर्देश

बैतूल। अपर कलेक्टर वंदना जाट ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं ध्यान पूर्वक सुनीं। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, बिजली, पानी सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। इस दौरान उन्होंने कई प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर मौके पर ही निराकरण कराया, वहीं शेष मामलों में समय-सीमा तय करते हुए अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती जाट ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई में दोबारा न आना पड़े। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर मकसूद अहमद, एसडीएम डॉ अभिजित सिंह ने भी नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस अवसर पर सभी

विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

संबल योजना का लाभ दिलाने की गुहार- जनसुनवाई में बैतूल के काजी जामठी निवासी सुशील परते ने संबल योजना के तहत लाभ नहीं मिलने की शिकायत की जिस पर अपर कलेक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारी को जांच कर आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए। आमला तहसील के ग्राम मोरखा निवासी सतीश बिन्झाड़े ने आवास बनाने के लिए ग्राम पंचायत के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया। प्राप्त आवेदन पर अपर कलेक्टर ने जनपद पंचायत आमला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवेदक की समस्या के निराकरण के निर्देश दिए।

अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश- भैंसदेही तहसील निवासी ओझा धुर्वे ने भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए आवेदन दिया। जिस पर अपर कलेक्टर ने भैंसदेही तहसीलदार को अवैध कब्जा पाए जाने पर हटाने के निर्देश दिए। आठनेर तहसील के ग्राम खापा निवासी वासुदेव खाकरे द्वारा भूमि की मेड़ तोड़े जाने की शिकायत पर अपर कलेक्टर ने आठनेर तहसीलदार को जांच कर प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बैतूल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने कलेक्ट्रेट परिसर में कानून व्यवस्था, सुरक्षा एवं शासकीय कार्यों की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत अब कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जारी निर्देशों के

अनुसार ज्ञापन सौंपने के लिए आयोजक को पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आवेदन में आयोजक सहित अधिकतम पांच व्यक्तियों के नाम, पते एवं मोबाइल नंबर का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। साथ ही ज्ञापन सौंपने की तिथि एवं समय भी निर्धारित करना आवश्यक रहेगा। निर्धारित समय से अधिकतम 30 मिनट की देरी ही मान्य होगी। अनुमति प्राप्त पांच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि सामूहिक रूप से ज्ञापन केवल कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्य द्वार क्रमांक-01 पर ही सौंपा जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर की 100 मीटर परिधि में किसी भी संगठन को सामूहिक रूप से प्रवेश करने, नारेबाजी करने अथवा धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा किसी भी रैली या जुलूस के आयोजन के लिए 48 घंटे पूर्व पुलिस को सूचना देना तथा सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है।

आदेश के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में लाठी-डंडे, पत्थर, घातक हथियार, ज्वलनशील पदार्थ, बारूद, पटाखे, पेट्रोल अथवा अन्य शस्त्र लेकर प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही परिसर में भारी एवं व्यावसायिक वाहनों के आवागमन पर भी रोक रहेगी। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा समूह के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह आदेश शासकीय आयोजनों, कार्यक्रमों, ड्यूटी पर तैनात शासकीय सेवकों, पुलिस बल एवं मजिस्ट्रेटों पर लागू नहीं होगा।

जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, किसानों की मांगें पूरी करना होगा नारे से गूंजा नगर, कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन

सोहागपुर। ब्लाक कांग्रेस के तत्वावधान में किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस परिवार एवं किसानों ने मुख्य बाजार से जुलूस निकाल कर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग कार्यालय पहुंचे। लेकिन यहां एसडीएम उपस्थित नहीं थीं। यहां पुष्पराज सिंह पटेल ने नेतृत्व में शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिसमें पुष्पराज सिंह पटेल के स्वर में स्वर मिलाते रहे उपस्थित जन। नारेबाजी में शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, किसानों की मूंग खरीदनी होगी, खरीदनी होगी, किसानों को डीजल देना होगा देना होगा। वहीं कांग्रेस जनों को पता चला कि एसडीएम जनपद पंचायत में हैं।तब सभी कांग्रेस जन जुलूस लेकर जनपथ पंचायत कार्यालय पहुंचे। यहां भी पहले ज्यादा उत्साहित होकर नारेबाजी की गई। जिसमें अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। बाद में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी तहसीलदार आर एस झरबड़े नायब तहसीलदार रणजीतसिंह चौहान आदि उपस्थित थे। ज्ञापन में कहा गया है कि सोहागपुर तहसील में मूँग की फसल पककर तैयार है। लेकिन मूँग ख़रीदी को लेकर शासन द्वारा कोई

उचित आदेश या प्रबंधन नहीं किए जा रहे हैं। जिससे क्षेत्र के किसानों में सरकार को लेकर काफ़ी नाराज़गी है। क्षेत्र के किसानों की ओर से ब्लॉक काँग्रेस परिवार माननीय कलेक्टर नर्मदापुरम को अनुविभागीय अधिकारी प्रियंका भल्लावी कै ज्ञापन सौंपती है। ज्ञापन में कहा गया है कि तहसील के किसानों की फसल की शीघ्र गिरदावरी कराई जाये और पंजीयन शुरू किया जाए। म प्र सरकार प्रति हेक्टेयर 12 क्विंटल मूँग खरीदी करे। प्रदेश सरकार सोहागपुर तहसील के किसानों की गेंहू और चना की फसल का भुगतान शीघ्र बकाया भुगतान किया जाए। आगामी फसल धान में पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद और यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करें अगर डीएपी नहीं है तो 12,32,16 ग्रोमोर की व्यवस्था करें। तहसील में किसानों के नामांतरण और सीमांकन की प्रक्रिया पूरी तरह विफल है। इसे प्रभावी तरीके से सुधारा जाए।आगामी धान की फसल के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीज़ल उपलब्ध कराया जाए। किसान फार्मर आई डी में एक साथ एक किसान के सारे खसरा जोड़ें जाएँ चाहे उस किसान की ज़मीन दो या उससे अधिक गाँव में ही क्यों न हों। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई कार्यवाही शासन द्वारा नहीं की गई ।तो काँग्रेस पार्टी सोहागपुर किसानों की लड़ाई सड़क पर लड़ने के लिए मजबूर होगी और उसकी जिम्मेदारी शासन की होगी। इस अवसर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता पुष्पराजसिंह पटेल, पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय, राजकुमार रघुवंशी, वकील प्रांजल तिवारी, किसान कांग्रेस अध्यक्ष गणेश अहिरवार, दंगल सिंह पटेल,ऋषभ दीक्षित, जिला जनपद पंचायत सदस्य दौलतराम पटेल, राकेश चौधरी, मनीष पटेल, पूर्व पार्षद मोहन कहार, इरफान खान,गुड्डु चौधरी ,राजा भैया पटेल माईकल खान आदि कई कांग्रेसी एवं किसान उपस्थित थे।

बांस शिल्पकला से रूबरू हुए जनजाति वर्ग के युवा-युवती

बैतूल। मध्यप्रदेश प्राद्योगिकी परिषद् भोपाल की योजनान्तर्गत बांस शिल्प कला और अनुसन्धान केंद्र भारत भारती परिसर में बांस शिल्प प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें बैतूल विकासखंड के 75 जनजाति युवा युवतियों ने बांस के सजावटी सामान, लेम्प, गुलदस्ता आदि बनाना सीखा। इस अवसर पर भारत भारती आईटीआई के प्राचार्य विकास विश्वास, प्रशिक्षण अधिकारी अखिलेश शर्मा, प्रशिक्षक नरेन्द्र मोहबे उपस्थित रहे। श्री शर्मा ने बताया कि हमारे जनजाति युवा पढाई के बाद नौकरियों की खोज में लगे रहते हैं। जबकि कौशल विकास के अनेक ऐसे काम है, जिनको बिना किसी लागत के सरलता से सीखे और अपनाये जा सकते हैं। बांस शिल्प उन्ही में से एक है। आज कल अपने घरों, उद्यानों की सजावट, बांस की कुर्सियां, फूलदान, लैंप आदि की बाजार में मांग भी है, व इस बाजार में संभावनाएं भी अधिक हैं। दूसरा पक्ष यह भी है कि इस काम में आंशिक लागत से भी यह स्वरोजगार अपनाया जा सकता है।

संक्षिप्त समाचार

मदिरा के अवैध विक्रय व संग्रहण के विरूद्ध 9 प्रकरण दर्ज

हरदा (निप्र)। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन के निर्देशन व जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के दल ने गत दिवस मदिरा के अवैध विक्रय, परिवहन व संग्रहण के विरूद्ध कार्यवाही की। जिला आबकारी अधिकारी श्री सुनील भोजने ने बताया कि इस दौरान आबकारी विभाग के दल ने जिले के टंकी मोहल्ला, बैरागढ़, ग्राम सुल्तानपुर, जिनवान्या, बालागांव, शिरी, कुकरावद में दबिश दी। दबिश के दौरान कुल 25 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं 490 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 के तहत कुल 9 प्रकरण दर्ज किये। जप्त मुद्देमाल का अनुमानित बाजार मूल्य 54 हजार रूपये है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिदिन योग कक्षाओं का आयोजन

बैतूल (निप्र)। 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में शासन के द्वारा प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से 7 बजे तक जिला जनसंपर्क कार्यालय के सामने स्थित भवन में निशुल्क योग कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। योग प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में आयोजित इन कक्षाओं में विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया जा रहा है। योग प्रशिक्षकों ने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की गई है।

पर्यावरण संरक्षण का संदेश लेकर निकली साइकिल रैली

बैतूल (निप्र)। जिला पंचायत द्वारा पर्यावरण संरक्षण पखवाड़े के तहत विश्व साइकिल दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को ग्राम पंचायत कढ़ाई में 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से फिट इंडिया अभियान एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया ।कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री हंसराज धुर्वे, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उपास्थित रही ।इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी दिलाई गई। जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री धुर्वे ने कहा कि साइकिल का नियमित उपयोग स्वास्थ्य संवर्धन के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस दौरान प्रतिभागियों ने साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

जिले में हरेक तहसील के 10 सबसे बड़े तालाबों की जानकारी एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही प्रस्तुत करें: कलेक्टर

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्रों की तहसीलों के अंतर्गत स्थित 10 सबसे बड़े तालाबों का विस्तृत विवरण तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि तालाबों एवं अन्य जल स्रोतों का संरक्षण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इनके अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक तहसीलदार अपने क्षेत्र के प्रमुख एवं बड़े तालाबों की सूची तैयार करें, जिसमें तालाब का नाम, क्षेत्रफल, वर्तमान स्थिति तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज जानकारी का उल्लेख किया जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि संबंधित तालाबों पर यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया गया है तो उसे हटाने के लिए अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन की दृष्टि से तालाबों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक जल स्रोतों पर हो रहे अतिक्रमण न केवल पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य में जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए सभी राजस्व अधिकारी गंभीरता के साथ अपने क्षेत्रों में तालाबों की स्थिति का सर्वेक्षण करें और अतिक्रमण की पहचान कर नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने यह भी निर्देश दिए कि जिन तालाबों पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा चुकी है, उनकी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। वहीं जिन स्थानों पर अतिक्रमण अभी भी मौजूद है, वहां प्रस्तावित कार्ययोजना एवं कार्रवाई की समय-सीमा भी स्पष्ट रूप से बताई जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जल स्रोतों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इस दिशा में राजस्व विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है और सभी अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा।

नकली खाद-बीज के विक्रय पर रोक लगाने के लिए करें नियमित जांच, अमानक सामग्री मिलने पर हो सख्त कार्रवाई - कलेक्टर

अपात्र हितग्राहियों के नाम हटाकर पात्र व्यक्तियों को जोड़ा जाए

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के समय-सीमा वाले प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और समय सीमा के भीतर सभी प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए।

बैठक मे कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए खाद-बीज विक्रय केंद्रों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए तथा नकली अथवा अमानक खाद-बीज के विक्रय पर प्रभावी रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण खाद बीज उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में कलेक्टर ने कृषि अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में संचालित खाद-बीज विक्रय केंद्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए। निरीक्षण के दौरान स्टॉक, गुणवत्ता, लाइसेंस तथा विक्रय संबंधी अभिलेखों की जांच की जाए। यदि किसी केंद्र पर अमानक अथवा नकली खाद-बीज का भंडारण या विक्रय पाया जाता है तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने कहा कि खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों की मांग के अनुरूप खाद एवं बीज की उपलब्धता बनाए रखना भी आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को प्रमाणित एवं गुणवत्तायुक्त बीजों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाए तथा किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जाए।

खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित पात्रता पर्चियों एवं राशन कार्डों का नियमित सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि अपात्र तथा मृत हितग्राहियों के नाम सूची से हटाए जाएं, ताकि वास्तविक एवं नए पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी पात्रता सूची का गंभीरता से परीक्षण करें तथा अपात्र एवं मृत हितग्राहियों के नामों को नियमानुसार हटाने की कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ऐसे परिवार, जो पात्र होने के बावजूद अभी तक सूची में शामिल नहीं हो सके हैं, उनके नाम प्राथमिकता के आधार पर जोड़े जाएं। उन्होंने हितग्राहियो की शत-प्रतिशत ईकेवाईसी कराने के भी निर्देश दिये।

बैठक के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के ने 05 जून से प्रारंभ हुए जनकल्याण अभियान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने अधिकारियों से कहा कि अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं के पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें समयबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि 12 जून से 18 जून तक आयोजित होने वाले शिविरों का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इन शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि शिविरों के संबंध में ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों एवं स्थानीय स्तर पर व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जाएं। साथ ही प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर आमजन को शिविरों की तिथि, स्थान एवं उपलब्ध सेवाओं की जानकारी दी जाए।

कलेक्टर ने जिले में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान की विभागवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को अभियान के कार्यों में गति लाने तथा निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण, जल संवर्धन एवं जनभागीदारी से जुड़े कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की गई। बैठक मे कलेक्टर ने कहा कि जो भी कार्य पूर्ण हो जायें उन्हें पोर्टल पर दर्ज किया जये। इस अभियान का उद्देश्य जल स्रोतों का संरक्षण करना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना तथा जल संकट के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करना है।

कलेक्टर श्री बालागुरू के ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वनाधिकार पट्टों के फौती नामांतरण के प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा लंबित मामलों में तेजी लाकर पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि नामांतरण संबंधी प्रकरणों में अनावश्यक विलंब न हो और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं। वनाधिकार पट्टों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि फौती नामांतरण की कार्यवाही संवेदनशील विषय है और इससे कई परिवारों के अधिकार जुड़े हुए हैं। इसलिए राजस्व, वन एवं संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए तथा आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए। बैठक में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरू के ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कोई भी छात्र-छात्रा ड्रॉपआउट न रहे। उन्होंने कहा कि जो बच्चों ने किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ रहे है या विद्यालय एवं महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है, उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।

फॉर्मर आईडी एवं ई-टोकन प्रणाली पर किसानों को दी जानकारी

बैतूल (निप्र)। कृषि विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विकासखंडों में किसानों को फॉर्मर आईडी, ई-टोकन विकास प्रणाली तथा प्राकृतिक खेती संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए रविवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

विकासखंड घोड़ाडोंगरी की ग्राम पंचायत पाढर में आयोजित फॉर्मर आईडी शिविर में किसानों को ई-टोकन विकास प्रणाली के माध्यम से खाद प्राप्त करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में उपस्थित किसानों को खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती, अंतर्वर्तीय फसल पद्धति तथा बुवाई की वैज्ञानिक विधियों के संबंध में भी जागरूक किया गया।

इसी प्रकार विकासखंड भीमपुर के ग्राम भीमपुर में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए तथा प्राकृतिक खेती अपनाने के लाभों की जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को ई-विकास प्रणाली के माध्यम से खाद उठाव की प्रक्रिया से विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया।

विकासखंड बैतूल में डीएसी कोर्स के अभ्यर्थियों को प्राकृतिक खेती के महत्व, संतुलित उर्वरक प्रबंधन तथा ई-विकास प्रणाली से खाद प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। अभ्यर्थियों को किसानों के बीच इन योजनाओं एवं तकनीकों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए भी निर्देशित किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस पर कृषि विभाग का पौधारोपण अभियान संपन्न

विदिशा (निप्र)। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर कृषि विभाग द्वारा करैयाखेड़ा रोड स्थित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना तथा अधिक से अधिक पौधारोपण को प्रोत्साहित करना रहा।

इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नीम एवं आम के पौधों का रोपण किया गया। पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, हरित क्षेत्र बढ़ाने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने का संदेश दिया गया। उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक दिन का अभियान नहीं, बल्कि सतत जनभागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी का विषय है।

कार्यक्रम में उप संचालक कृषि श्री के. एस. खपेड़िया, सहायक संचालक कृषि श्रीमती अविना सिंह परिहार, सहायक संचालक उद्यान श्री श्यामलाल सोलंकी, जिला सलाहकार कृषि डॉ. डी. के. तिवारी तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री विशाल यादव सहित विकासखंड के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने उपस्थित कर्मचारियों से अधिकाधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण के महत्व पर चर्चा करते हुए बताया गया कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को शुद्ध बनाते हैं, बल्कि जल संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित यह कार्यक्रम हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण की दिशा में कृषि विभाग की सार्थक पहल के रूप में सराहा गया।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन को स्वस्थ जीवन की आधारशिला बताया, खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन का दिया संदेश

विदिशा (निप्र)। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन, द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को सुरक्षित, स्वच्छ एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों के महत्व तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में नागरिकों, खाद्य कारोबारकर्ताओं, विद्यार्थियों तथा विभिन्न सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय में स्वच्छता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने उपस्थित लोगों को खाद्य सामग्री खरीदते समय एफएसएसएआई लाइसेंस अथवा पंजीयन, निर्माण तिथि, उपयोग अवधि (एक्सपायरी डेट) तथा पैकेजिंग की सावधानीपूर्वक जांच करने की सलाह दी।

विशेषज्ञों ने स्वस्थ एवं संतुलित आहार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट की पहचान तथा खाद्य जनित रोगों की रोकथाम के उपायों की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम में बताया गया कि सुरक्षित भोजन न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य की रक्षा करता है, बल्कि एक स्वस्थ, सक्षम और सशक्त समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की गई कि वे केवल स्वच्छ, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रमाणित खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करें। साथ ही किसी भी प्रकार की खाद्य मिलावट, दूषित खाद्य सामग्री अथवा खाद्य सुरक्षा संबंधी अनियमितताओं की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप वर्मा, श्रीमती किरण श्रीवास्तव एवं सुश्री कुदसिया खान ने उपस्थित नागरिकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया तथा कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए पौष्टिक एवं संतुलित खाद्य पदार्थों के सेवन की सलाह दी।कार्यक्रम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती मिताली मेहरा, श्री रवि तलरेजा (अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स), श्री महिपाल सिंह राजपूत एवं श्री आनंद अग्रवाल (होटल रेस्टोरेंट एसोसियेशन), श्री रामूराम जाट (राजस्थान स्वीट, किराना एवं व्यापार संघ), श्री श्याम सुंदर शर्मा (वरिष्ठ समाजसेवी, अपना घर) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी एवं बेतवांचल कॉलेज के विद्यार्थियों ने सक्रिय सहभागिता करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

कार्यक्रम के अंत में सुरक्षित भोजन, स्वस्थ जीवन और खाद्य सुरक्षा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया गया तथा आमजन से खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया गया।

जिले में 'संडे ऑन साइकिल' रैली का हुआ आयोजन

हरदा (निप्र)। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा फिट इंडिया मिशन के तहत रविवार को विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर जिलेभर में 'संडे ऑन साइकिल' अभियान आयोजित किया गया।

इसी क्रम में जिला स्तरीय साइकिल रैली का आयोजन घंटाघर क्षेत्र से किया गया। रैली को जिला शिक्षा अधिकारी श्री डी.एस. रघुवंशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप संचालक सामाजिक न्याय श्री कमलेश सिंह सहित अन्य जिला अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं नागरिक उपस्थित रहे।जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ब्लॉक समन्वयक सुश्री सलमा खान ने बताया कि यह जागरूकता रैली घंटाघर से प्रारंभ होकर चांडक चौराहा, पोस्ट ऑफिस चौक, परशुराम चौक, काली मंदिर, सनफ्लावर स्कूल मार्ग से होते हुए नेहरू स्टेडियम हरदा के गेट क्रमांक-4 पर समाप्त हुई।विश्व साइकिल दिवस पर आयोजित इस रैली का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को फिटनेस, पर्यावरण संरक्षण और साइकिल के नियमित उपयोग के प्रति जागरूक करना था।

फसल गिरदावरी कार्य में तेजी लाते हुए इसे शीघ्र पूर्ण कराएं राजस्व अधिकारी- कलेक्टर श्री विश्वकर्मा

टीएल बैठक में कलेक्टर ने की विभागीय कार्यो तथा योजनाओं की समीक्षा

रायसेन (निप्र)। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित टीएल में कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा द्वारा समय सीमा वाले शासकीय पत्रों, सीएम हेल्पलाईन, अभियानों, योजनाओं सहित विभागीय कार्यो की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों, सीमांकन, बंटवारा, नामांतरण आदि प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार जानकारी लेते हुए सभी एसडीएम एवं तहसीलदारों को निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम से कहा कि राजस्व प्रकरणों का समयावधि में अंतिम निराकरण जरूरी है। इसी प्रकार लोक सेवा गारंटी अधिनियम में प्राप्त आवेदनों का भी अंतिम समयावधि के पूर्व निराकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने गिरदावरी कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में अभी तक लगभग 30 प्रतिशत कार्य ही हुआ है। इसे पूर्ण कराने के लिए सभी एसडीएम गिरदावरी कार्य में तेजी लाएं तथा नियमित मॉनीटरिंग करें। उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री की भी समीक्षा करते हुए कहा कि ई-विकास टोकन प्रणाली में किसानों के पंजीयन हेतु फार्मर रजिस्ट्री होना जरूरी है, सभी एसडीएम फार्मर रजिस्ट्री का शत-प्रतिशत कार्य शीघ्र पूर्ण कराएं। इसी प्रकार सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि सभी तहसीलदार न्यायालय में बैठे तथा प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण कराएं, यह सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने खाद वितरण की जानकारी लेते हुए कहा कि कृषि विभाग, राजस्व विभाग और पंचायत विभाग का मैदानी अमला ई-विकास टोकन प्रणाली की जानकारी सभी किसानों तक पहुंचाएं, जिससे कि सभी किसानों का पोर्टल पर पंजीयन हो। इसी प्रकार राजस्व वसूली के संबंध में भी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिए गए। उन्होंने पीएचई, सामाजिक न्याय, जनजातीय कार्य विभाग, वन विभाग, एमपीईबी के अधिकारियों तथा एसडीएम से गत जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी लेते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का सभी अधिकारी गंभीरता से निराकरण कराते हुए प्रतिवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही आवेदन के निराकरण संबंधी कार्यवाही से आवेदक को अवगत कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने आगामी योग दिवस पर जिले में सामूहिक योगाभ्यास आयोजन के संबंध में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती की जानकारी देते हुए इसके लिए किसानों को प्रोत्साहित करने शिविर आयोजित किए जाने पर भी चर्चा कर कृषि अधिकारी को निर्देश दिए। इसी प्रकार संबल और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन कराने, जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किए जा रहे कार्यो, उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में जबावदावा दर्ज कराने के संबंध में भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए।

राइट क्लिक

नाम भले 'कॉकरोच' हो, लेकिन एप्रोच में संजीदा होना होगा..

अजय बोकिल

लेखक सुबह सवेरे के कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।
संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

सवाल देश में समानांतर तैर रहे हैं। पहला तो सोशल मीडिया जनित 'कॉकरोच जनता पार्टी' का एक राजनीतिक दल और उसके द्वारा प्रणीत कॉकरोच आंदोलन का भविष्य क्या है और दूसरा, विपक्षी इंडिया अलायंस नई परिस्थितियों में क्या नए सिरे से दम मारेगा या फिर यह भी एक प्रतिपक्ष की खानापूर्ति ही है? ताजा घटनाक्रम में भाजपा और मोदी सरकार के लिए चिंता का विषय यह है कि भले ही देश में मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के साथ अभी खुलकर नहीं आई हैं, लेकिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की 7वीं बैठक में शामिल 23 पार्टियों ने सीजेपी की उस मांग को दोहराया है, जिसमें नीट पेपर लीक घोटाले में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की बात कही गई है। यह भी संभव है कि कॉकरोच आंदोलन अपनी वर्चुअल सीमा को लांघ कर एक्चुअल में बदल जाए तो विपक्षी दल उसके साथ खुलकर आ जाएं। कुछ दल तो इसे अभी भी नैतिक समर्थन दे रहे हैं। धर्मेन्द्र प्रधान पर 'इंडिया अलायंस' के स्टैंड से मोदी सरकार पर कुछ दबाव तो बनेगा, बावजूद इस सच्चाई के कि बीजेपी में नैतिक आधार पर इस्तीफे नहीं होते। जिसे मंत्रिमंडल से बाहर करना होता है, वह किसी फेरबदल में एक झटके में बाहर कर दिया जाता है। जाहिर है कि धर्मेन्द्र प्रधान के कामकाज को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का क्या आकलन है, यह तभी पता चलेगा, जब केन्द्रीय मंत्रिमंडल में बहुप्रतीक्षित विस्तार या फेरबदल होगा। धर्मेन्द्र प्रधान खुद इस्तीफा नहीं देंगे। यह भी संभव है कि उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे विभाग में भेज दिया जाए। जहां तक शिक्षा क्षेत्र में संघ का एजेंडा लागू करने की बात है तो धर्मेन्द्र प्रधान यह काम पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में प्रवेश और बोर्ड परीक्षाओं की पवित्रता पर जिस ढंग से दाग लग रहे हैं, उससे विभाग पर उनकी पकड़ और परफार्मेंस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। इस स्थिति को पीएम भी अफोर्ड शायद ही कर पाएं। क्योंकि इससे भारत के साथ-साथ विदेशों में भी हमारी शिक्षा प्रणाली की साख को संदेह की निगाह से देखा जाने लगा है।

अब सवाल सीजेपी (कॉजपा) का। सीजेपी के संयोजक अभिजीत दिपके ने अमेरिका से लौटते ही 6 जून को जंतर-मंतर पर अपने कुछ साथियों के साथ प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग भी धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा ही है। दिपके ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर एक हफ्ते के भीतर प्रधान का त्यागपत्र न हुआ तो वो अपने आंदोलन को देशभर में फैलाएंगे। दिपके नीट परीक्षा में पेपर लीक के साथ-साथ बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे स्थायी मुद्दे भी उठा रहे हैं, जिनसे आज का युवा परेशान है। जमीनी स्तर पर इस आंदोलन से भारत में युवा खासकर जेन जी कितनी तादाद में जुड़ेंगे, यह अभी देखने की बात है। बकौल दिपके सोशल मीडिया पर उनके 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर बन चुके हैं और 2 लाख से अधिक युवाओंने सीजेपी की सदस्यता के लिए नाम रजिस्टर कराया है।

सरकार भी सीजेपी के इस उभार और गतिविधि को बहुत चौकस नजरों से देख रही है। क्योंकि यह आंदोलन पारंपरिक राजनीति करने वालों को कितना हिट करेगा अथवा कितना सपोर्ट करेगा, इसका आकलन आसान नहीं है। दूसरे, अगर इस आंदोलन ने सचमुच विराट रूप ले लिया तो विश्व में जन आंदोलनों के इतिहास का यह नया अध्याय होगा, जिसकी एक झलक हम नेपाल और श्रीलंका में देख चुके हैं। फिलहाल सच्चाई यह है कि इस कॉकरोच आंदोलन को लेकर लोकतंत्र के दोनों प्रमुख घटक सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही चौकन्ने हैं। सरकार को डर है कि अगर यह मुहिम युवाओं के जन आंदोलन में बदलने लगी तो सत्ता में बने रहने की जुगत और विकास का रोडमैप ही बदलना पड़ेगा। हालांकि सरकार अभी इस आंदोलन की गंभीरता, गहराई और व्यापकता को समझने की कोशिश कर रही है, इसलिए उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। जबकि कई विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस में चिंता इस बात की है कि आंदोलन का परोक्ष उद्देश्य देश में कांग्रेस और राहुल गांधी की सुधरती छवि को 'डेंट' करना है। राहुल भक्तों की राय में राहुल गांधी के कमजोर होने का मतलब समूचे विपक्ष का कमजोर होना है। वाम और आप के कुछ नेताओं तथा सिविल सोसाइटी के कुछ लोगों ने कॉकरोच आंदोलन को अपना समर्थन इस उम्मीद में दिया है कि युवा मन के आक्रोश की यह चिंगारी देर-सवेर ज्वाला बनकर धधकेगी, जिसका इस्तेमाल केन्द्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार को बेदखल करने में किया जा सकता है। हालांकि डर उनके मन में भी है कि कॉकरोच आंदोलन को यह सपोर्ट कहीं भस्मासुर न बन जाए। बहुत से कांग्रेसी इसकी तुलना दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अन्ना आंदोलन से कर रहे हैं, जिसे बाद में भाजपा हाई जैक कर लिया जबकि दिल्ली में उसकी राजनीतिक फसल आम आदमी पार्टी ने काट ली। इस सोच में यह शंका भी निहित है कि इस आंदोलन से युवाओं की मांगें पूरी हों न हों, लेकिन यह कॉकरोच पार्टी कांग्रेस जैसे दल की राजनीतिक पूंजी को ही चट न कर जाए। जहां तक कॉकरोच जनता पार्टी के एक जनआंदोलन में बदलने की संभावना का सवाल है तो इसमे वक्त लगेगा। भले ही इसके प्रणेता अभिजीत दिपके ने कहा हो कि वो इस आंदोलन को सभी गांव-शहरों तक ले जाएंगे। लेकिन बगैर किसी स्पष्ट विचारधारा और उद्देश्य, वैकल्पिक विचार, दूरगामी लक्ष्य, प्रभावी संगठन और समर्पित कार्यकताओं की फौज के बगैर कोई आंदोलन किसी क्रांतिकारी सैलाब में तब्दील नहीं हो सकता। वैसे भी उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी से प्रभावित युवाओं का एक सीमित वर्ग है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जरूर ऐसा मुद्दा हो सकता है, जो लाखों युवाओं को जोड़े। लेकिन भारत में भ्रष्टाचार का विरोध अमूमन तभी तक होता है, जब तक कि दूसरों को इसका मौका न मिले। वैसे भी राजनीतिक आंदोलन कोई टीवी रिमोट कंट्रोल का बटन नहीं है, कि जब चाहा चैनल बदल दिया। जेन जी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उसमें सातत्य की कमी है। वह बहुत ज्यादा जल्दी में दिखती है और बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। किसी एक मुद्दे, विचार, पसंद या आग्रह पर धैर्य के साथ टिके रहना और उसके लिए संघर्ष करने की फितरत उसमें अपवादस्वरूप ही देखने को मिलती है। ज्यादा दूर क्यों जाएं, शादी की बारात में कानफोडू शोर के साथ बेतरतीब नाचते युवा किसी एक गाने पर भी दो घड़ी टिकना नहीं चाहते। बुद्धि से कुशाग्रतर होने के बाद भी आचरण में एक सतहीपन और कॉकटेल सोच उनकी जिंदगी पर तारी है, जो जज्बात से लेकर जीवन के हर व्यवहार में साफ झलकता है।

ऐसे में पारंपारिक राजनीतिक औजारों के बगैर महज कॉकरोच मानसिकता के साथ कोई देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना बेहद कठिन है। फिलहाल जो संवेग बना है, उसे मजबूत करने और गति देने के लिए दिपके को संगठन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। आंदोलन की दीर्घकालिक योजना बनानी होगी। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि पारंपरिक राजनीतिक दल भी उसमें शामिल हो जाएं। यानी नाम भले ही कॉकरोच हो, लेकिन एप्रोच में उसे संजीदा यानी बिज्जू (हनी बैजर) की तरह होना होगा। ऐसा हो सका तो यकीनन सरकारों और कई राजनीतिक पार्टियों की मुश्किलें बढ़ेंगी।

वरिष्ठजन की सेवा ही मानवता की सच्ची सेवा : मंत्री कुशवाह

भोपाल (नप्र)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने मंगलवार को शाहजहानाबाद स्थित आसरा वृद्धाश्रम पहुंचकर वरिष्ठजन

के साथ समय व्यतीत किया और उनकी सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वृद्धाश्रम में आयोजित धार्मिक एवं सेवा कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री कुशवाह ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुंदरकांड पाठ में सहभागिता की। मंत्री श्री कुशवाह ने वृद्धाश्रम में निवासरत वरिष्ठ नागरिकों से आत्मीय संवाद कर कुशलक्षेम जानी तथा उनकी आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मंत्री श्री कुशवाह ने वृद्धजन को वस्त्र भेंट कर भोजन प्रसादी भी वितरित की। उन्होंने कहा कि समाज के वरिष्ठजन अनुभव, संस्कार और परंपराओं के संवाहक हैं। उनका सम्मान, सेवा और देखभाल करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व है। मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि वृद्धजन के स्नेहपूर्ण आशीर्वाद और उनके चेहरे पर आई मुस्कान से उन्हें आत्मिक शांति एवं संतोष की अनुभूति हुई। उन्होंने समाज से वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का भाव बनाए रखने का आहवान किया। वृद्धाश्रम के बुजर्गों ने मंत्री श्री कुशवाह के इस आत्मीय प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने वरिष्ठजन की सेवा को भारतीय संस्कृति और मानवीय मूल्यों का सशक्त प्रतीक बताया।

सिंगरौली के अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड बना 'डॉक्टर'

ड्रिप लगाते हुए वीडियो बनाने पर कहा- क्या कर सकते हो तुम?

सिंगरौली (नप्र)। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत किसी से छुपी नहीं है। सिंगरौली जिले के चितंरगी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड मरीज को ड्रिप लगा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप- वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सिक्योरिटी गार्ड को ड्रिप लगाते हुए देखकर लोगों का कहना है कि यह सीधे तौर पर मरीजों की जान के खिलवाड़ है। चितरंगी प्रदेश के पंचायत ग्रामीण विकास राज्यमंत्री राधा सिंह का गृह क्षेत्र भी है।

अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई- स्थानीय लोगों का आरोप है कि चितरंगी अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। यहां इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टरों के बजाय गार्ड और वार्ड बॉय के भरोसे चल रही है। वहीं, डॉक्टर और जिम्मेदार स्टाफ अक्सर ड्यूटी से नदारद रहते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले राकेश मौर्य ने जब इसका विरोध किया तो कथित तौर पर सुरक्षा गार्ड ने जवाब दिया कि क्या कर सकते हो, हटवा दो मुझे।

सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो- यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राकेश का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अस्पताल में वार्ड बॉय द्वारा इंजेक्शन लगाने और ड्रिप चढ़ाने के कई वीडियो सामने आ चुके हैं, जिससे साफ है कि व्यवस्था में गंभीर खामियां बनी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि दोपहर करीब 2 बजे जब यह घटना हुई, उस समय ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और जिम्मेदार स्टाफ आखिर कहां थे? और मरीजों के जीवन के साथ इस तरह का जोखिम क्यों लिया जा रहा है? स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय जांच कर जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

खुले में कचरा फेंका, जलाया तो जुर्माना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर मीटिंग, आरोप पर कांग्रेस पार्षद हकीकत देखने कचरा कैफे पहुंचे

भोपाल (नप्र)। भोपाल के आईएसबीटी स्थित निगम के मीटिंग हॉल में मंगलवार को ठोस अपशिष्ट एवं प्रबंधन के नए नियमों पर प्रजेंटेशन दिया गया। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी की मौजूदगी में एक्सपर्ट अतुल खरे ने बताया कि खुले में कचरा फेंक या जलाया तो निगम सख्ती करते हुए जुर्माना करेगा। बिना निगम की अनुमति से यदि 100 लोगों का कार्यक्रम भी कर रहे हैं तो निगम को 3 दिन पहले जानकारी देना होगी।

मीटिंग में कांग्रेस पार्षद देवांशु कंसाना ने कहा कि मेरे वार्ड की एक झुग्गी से आंधी की वजह से गिरा पेड़ छह दिन में ही उठा। यदि एक छोटे से काम में इतना वक्त लगेगा तो समझ सकते हैं कि काम की रफ्तार कितनी है? इससे मैं हताश हूं।

कंसाना की बात पर बीजेपी पार्षदों की आपत्ति- बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षद कंसाना ने गिरे पेड़ को हटाने और सफाई व्यवस्था पर जब बात की तो बीजेपी पार्षद बृजला सचाण ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हमारे यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्य बीजेपी पार्षदों ने भी यह बात दोहराई।

महापौर मालती राय ने कहा कि रात्रिकालीन सफाई कहां होती है? ये फील्ड में जाने वाले पार्षदों को पता होता है। वॉट्सएप पर जानकारी नहीं मिलेगी। कई पार्षद ऐसे हैं, जिन्हें सफाई से जुड़ी हर जानकारी है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कर्मचारी कम है या ज्यादा। बैठक के आखिरी में भी महापौर राय ने पार्षद कंसाना की बात पर आपत्ति ली।

कांग्रेस पार्षदों ने कई सवाल भी उठाए

इससे पहले मोहम्मद सरवर, योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान, मो. रियाज, शिरीन खान, अजीजउद्दीन समेत कई कांग्रेस पार्षदों ने सवाल भी उठाए। इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे मो. सरवर ने कहा कि पॉलीथिन पर भोपाल में ठोस कार्रवाई नहीं होती। सख्ती करेंगे तो ही ये नियम लागू होंगे। सूखा-गीला कचरा अलग-अलग उठाया जाता है, लेकिन कई क्षेत्रों में अलग ही तस्वीर है। यदि नाली साफ की जाती है तो कचरा बाहर ही रख दिया जाता है, क्योंकि गाड़ी वाले ये ले जाते नहीं है। ऐसे में यही कचरा सूखने के बाद इधर-उधर फेलता है। सफाई से जुड़ी कई दिक्कतें हैं, लेकिन उन्हें दूर करने की बात नहीं हो रही। सिर्फ कानून बनाने का ही प्रजेंटेशन हुआ है। पहले ही हम आम जनता से स्वच्छता शुल्क वसूल रहे हैं। नए नियमों से और बोझ पड़ेगा। कई जगह तो ड्राइवर ही गाड़ी में कचरा भरवा रहे हैं। पार्षद गुड्डू चौहान ने कहा कि यहां नए नियम की बात तो की जा रही है, लेकिन क्या हमारे पास संसाधन है? पैसा है? सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। वार्ड की कचरा गाड़ी यदि खराब हो जाए तो उस वार्ड का कचरा 5 दिन तक नहीं उठता है।

प्रदेश में अगले हफ्ते आ सकता है मानसून

इंदौर-जबलपुर से एंट्री संभव ; आज 18 जिलों में आंधी-बारिश, आज से 2 दिन हीटवेव चलेगी

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री अगले हफ्ते 15 से 18 जून के बीच होगी। इससे पहले प्री-मानसून एक्टिविटी जारी रहेगी। अनुमान के मुताबिक, मानसून इंदौर और जबलपुर संभाग के छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, बालाघाट, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर या बैतूल जिले से प्रदेश में एंटर कर सकता है।

इससे पहले प्रदेश में आंधी-बारिश जारी रहेगी। मंगलवार को 20 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश होने का अलर्ट है। इनमें बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया और शहडोल शामिल हैं।

10-11 जून को लू का भी अलर्ट

मौसम केंद्र भोपाल की माने तो अगले 3 दिन यानी, 9, 10 और 11 जून को प्रदेश में आंधी, बारिश के साथ गर्मी का असर भी बना रहेगा। 10 और 11 जून को प्रदेश के 5 जिले- भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में हीटवेव (लू) का अलर्ट भी है।

एमपी में पारा 42 डिग्री से ऊपर, ग्वालियर-जबलपुर में भी ज्यादा

प्रदेश में आंधी-बारिश के दौर के बीच गर्मी का असर भी है। सोमवार को पारा 42 डिग्री से ऊपर रहा। प्रदेश के 5 बड़े शहरों में ग्वालियर में सबसे ज्यादा 41.6 डिग्री, जबलपुर में 40 डिग्री, उज्जैन में 39.5 डिग्री, भोपाल में 38.7 डिग्री और इंदौर में 38.6 डिग्री रहा।

मंडला में पारा सबसे ज्यादा 42.5 डिग्री दर्ज किया गया। छिंदवाड़ा में 42.1 डिग्री, खजुराहो में 42 डिग्री, दमोह में 41.8 डिग्री, मलाजखंड में 41.7 डिग्री, राजगढ़ में 41.6 डिग्री, नरसिंहपुर, दतिया-नौगांव में 41.4 डिग्री, शाजापुर में 41.3 डिग्री, खंडवा में 41.1 डिग्री और गुना में 41 डिग्री रहा। खरगोन, सतना, रतलाम, टीकमगढ़, उमरिया और शिवपुरी में भी तापमान 40 डिग्री से ऊपर ही दर्ज किया गया।

महिला की हत्या, कुल्हाड़ी से काटे दोनों पैर

भोपाल (नप्र)। भोपाल के नजीराबाद क्षेत्र में 60 वर्षीय महिला की हत्या के बाद उसके दोनों पैर कुल्हाड़ी से काटकर चांदी के कड़े लूट लिए गए। महिला का हाथ का पंजा भी गायब मिला। चार दिन बाद शेषापुरा के जंगल में उसका सड़ा-गला शव बरामद हुआ। पुलिस ने गांव के ही जसवंत गुर्जर को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली।

बेटे से मिलवाने का झांसा देकर ले गया- मृतका बादाम बाई (60) बैरसिया क्षेत्र के पथरिया गांव की रहने वाली थीं। 4 जून को गांव का ही परिचित जसवंत गुर्जर

बादाम बाई, मृतक

उन्हें बेटे रवि से मिलवाने की बात कहकर बाइक पर बैठाकर ले गया था।

रवि गांव में ही रहता है, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण वह करीब आठ दिन से घर नहीं आया था। गांव वालों के मुताबिक आरोपी जसवंत रवि को अच्छी तरह जानता था और कई बार उसके साथ देखा गया था। इसी वजह से महिला ने उस पर भरोसा कर लिया।

आरोपी ने ही बताई शव की जानकारी- 6 जून को परिजनों ने बैरसिया थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और जसवंत गुर्जर पर संदेह जताया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने ही पुलिस को बताया कि महिला का शव शेषापुरा के जंगल में पड़ा है। इसके बाद पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे।

शेषापुरा के जंगल में महुए के पेड़ के नीचे महिला का शव मिला। शव करीब चार-पांच दिन पुराना था और सड़-गल चुका था। शव में कीड़े पड़ चुके थे। महिला के दोनों पैर टखनों के पास से कटे हुए थे और एक हाथ का पंजा भी गायब था। पैरों में पहने चांदी के कड़े नहीं मिले।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने पहले महिला का गला दबाकर हत्या की। इसके बाद कुल्हाड़ी से दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े निकाल लिए।

10 साल पुराने हवाई घोटाले ने उड़ाई एमपी के आईएएस अफसरों की हवाइयां, लोकायुक्त ने फिर खोली फाइल, गाज गिरना तय

उज्जैन (नप्र)। मध्य प्रदेश लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना ने करीब 10 साल पुराने 'यश एयरवेज' हवाई पट्टी घोटाले में बेहद आक्रामक रुख अपना लिया है। लोकायुक्त ने राज्य सरकार के उस फैसले को ठेंगा दिखा दिया है, जिसके तहत पिछले साल सभी आरोपी आईएएस अफसरों को अभियोजन मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। अब लोकायुक्त ने सीधे सामान्य प्रशासन विभाग को चिट्ठी लिखकर यह मामला केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजने का निर्देश दिया है। यह पूरा विवाद उज्जैन की दताना हवाई पट्टी से जुड़ा है। साल 2006 में राज्य सरकार ने इसके रखरखाव और संचालन का जिम्मा एक निजी कंपनी यश एयर लिमिटेड को सौंपा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस कंपनी को नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपये के अनुचित लाभ दिए गए, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। हाई कोर्ट द्वारा 2020 में

एफआईआर रद्द करने से इनकार के बाद इस जांच ने गति पकड़ी थी।

दताना एयरस्ट्रिप का खेल: निजी कंपनी यश एयर लिमिटेड को बिना भुगतान और ठप कामकाज के बावजूद 2.66 करोड़ रुपये के रेनोवेशन का फायदा पहुंचाया गया।

रात्रिकालीन शुल्क की माफी: कंपनी को नाइट पार्किंग चार्ज से भी पूरी छूट दी गई, जिससे सरकार को सीधा नुकसान हुआ।

राज्य 9 लोकायुक्त: साल 2025 में एमपी सरकार ने अफसरों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने से मना कर दिया था, जिससे तत्कालीन लोकायुक्त और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच तल्खी बढ़ गई थी।

केंद्र का नियम बना हथियार: लोकायुक्त ने 1999 के एक डीओपीटी सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि आईएएस अखिल भारतीय सेवा के तहत आते हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई का अंतिम फैसला राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार करेगी।

अफसरों में खलबली: लोकायुक्त के इस कदम से मध्य प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप है, क्योंकि इस मामले में कई रिटायर्ड और वर्तमान शीर्ष अधिकारी फंसे हुए हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपीई के महानिदेशक योगेश देशमुख ने साफ किया है कि राज्य सरकार का पिछला आदेश कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं था। चूंकि आरोपी ऑल इंडिया सर्विसेज़ से हैं, इसलिए सक्षम प्राधिकारी केवल केंद्र सरकार ही है।